वर्ष- 03 अंक -12 मई 2026 मूल्य - 50 रु.

लाईफ वर्सिटी

अखिल भारतीय पंचायत परिषद छत्तीसगढ़ का मुखपत्र

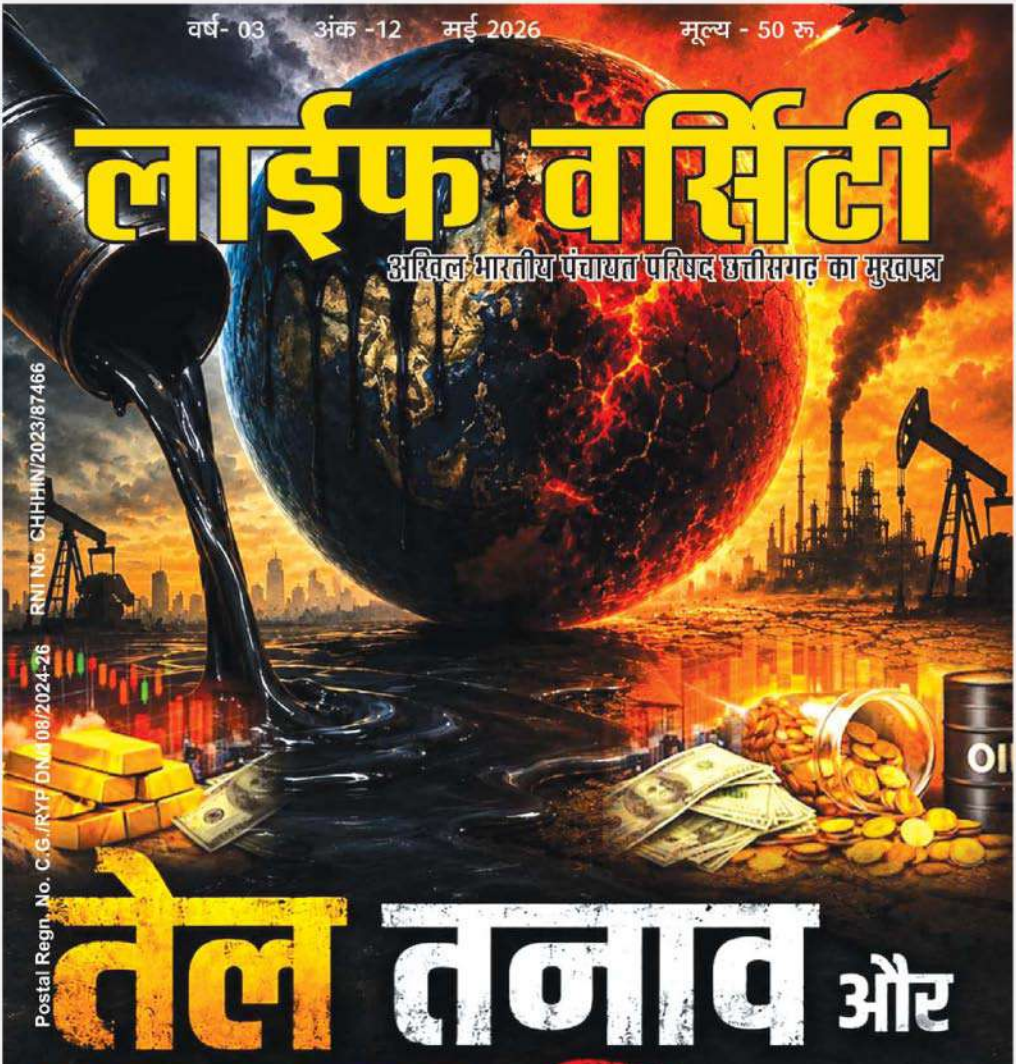

Postal Regn. No. C.G./RYP DN/08/2024-26 RNI No. CHHHIN/2023/87466

तेल तनाव और तपता विश्व

संयम और स्वदेशी की पुकार

T3 Team | Trust | Technology

अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़
रोशन छत्तीसगढ़

Major Highlights

20 ज़िले | **10** लाख संतुष्ट मरीज़ | **03** लाख सफल सर्जरी

सभी प्रकार के TPA एवं इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से ईलाज की सुविधा उपलब्ध है।

Trust

"Good facility and good behavior of all staff and doctors also good people's"
★★★★★

"We have sutesfie of his service, staff nurse and hospital cleaning."
★★★★★

"Quality treatment with highly qualified professionals"
★★★★★

Team

AIIMS दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई, एल. वी. प्रसाद हैदराबाद, नारायण नेत्रालय बेंगलुरु एवं अरविंद आई केयर कोयंबटूर से प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञों की टीम,

Dr. Charudutt Kalamkar
Cataract & Glaucoma & Pediatric Specialist

Dr. Anil Gupta
Comprehensive Eye Care Specialist

Dr. Amrita Mukherjee
Cornea & Glaucoma Specialist

Dr. Mayank Dubey
Cataract Specialist

Dr. Jayesh Patil
Retina Specialist

Dr. Rohit Rao
Phaco & Oculoplasty Specialist

Dr. Shubhank Khare
Retina Specialist

Dr. Patel Bhavin
Cataract & Pediatric Specialist

Dr. Jagdish Kumar
Comprehensive Eye Care Specialist

Dr. Meenakshi Masih
Glaucoma Specialist

Dr. Ruchita Rathi
Comprehensive Eye Care Specialist

Dr. Snigdha K Saxena
Comprehensive Eye Care Specialist

Dr. Jayant Ekka
Cataract Specialist

Google
★★★★★ 4.7 Star Rating

Technology

श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल

रायपुर (छ.ग.)
कलर्स मॉल के सामने, गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने,
मुस्कान रेसीडेंसी के पास, लालपुर, पचपेड़ी नाका, न्यू धमतरी रोड,

www.sgveh.com | +91 9644902896

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

सलाहकार मण्डल

डॉ अनिल गुप्ता	रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान	रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल	नई दिल्ली
प्रो तपन मोहन्ति	ओड़िसा

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी,
कलर्स मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.), मो. 88171-94979

विशेष सहयोग

अ.भा. पंचायत परिषद

नितीन गड़करी
संरक्षक

वाल्मिकी प्रसाद सिंह
अध्यक्ष

वैभव डांगे
राष्ट्रीय महासचिव

डॉ. रूद्रभानु
राष्ट्रीय महासचिव

परिकल्पना- रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर

04 युद्ध की आशंका, आर्थिक अनुशासन और वर्क फ्रॉम होम का विकल्प

10 सौम्यता में सख्ती विष्णुदेव साय की प्रशासनिक शैली

12 जनविश्वास और जवाबदेही के नए अध्याय–सुशासन तिहार

18 आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव पंचायती राज

20 परिवार, पंचायत और ग्राम स्वराज : एक राष्ट्रीय सामाजिक

24 हर काल में महिलाएं ही क्यों बनती है मोहरा

क्या खत्म हो रही है क्षेत्रीय राजनीति 6
बदलती भाजपा ,संगठन, सत्ता में नए..... 8
क्या जड़ों से कट रही ग्राम व्यवस्था?..... 17
पंचायत से राष्ट्र निर्माण तक अखिल 18
क्या महिलाएं सचमुच सशक्त हुई हैं? 25
पिंजड़े का बंद तोता या पहाड़ी मैना ? 27

SCAN & PAY

UPI ID: 329944413263914@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सत्ती बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

संयम और स्वदेशी की पुकार

> भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति अधिक गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें अब भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर निर्भर हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खपत कम करने, सोना-चांदी की खरीद पर संयम बरतने और विदेश यात्राओं को सीमित करने की अपील की है।

■ नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, बल्कि उनका प्रभाव सीधे आम आदमी की रसोई, जेब और भविष्य पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, अमेरिका-ईरान के बीच तीखी बयानबाज़ी, कमजोर पड़ते युद्धविराम और परमाणु हथियारों की आशंकाओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। तेल उत्पादक क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति का अर्थ केवल सैन्य संघर्ष नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महंगाई, आर्थिक दबाव और अनिश्चितता का नया दौर शुरू होना भी होता है।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति अधिक गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें अब भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर निर्भर हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खपत कम करने, सोना-चांदी की खरीद पर संयम बरतने और विदेश यात्राओं को सीमित करने की अपील की है। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक आर्थिक दबावों की चेतावनी भी है।

भारत हर वर्ष लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का कच्चा तेल और करीब 7 लाख करोड़ रुपये का सोना विदेशों से खरीदता है। इन दोनों का भुगतान डॉलर में होता है। यानी जितना अधिक आयात, उतनी अधिक डॉलर की मांग। डॉलर महंगा होता है तो रुपया कमजोर पड़ता है, और फिर वही तेल व सोना और अधिक महंगे हो जाते हैं। यह एक ऐसा आर्थिक चक्र है जो सीधे महंगाई को बढ़ाता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है।

ईरान संकट के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट इसी दबाव की ओर संकेत करती है। तेल की कीमतें लगातार ऊँचे स्तर पर बनी हुई हैं। सोने का आयात बिल भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है। विदेश यात्राओं और विलासिता आधारित खर्चों में वृद्धि ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में यदि देशवासी थोड़े संयम का परिचय दें तो

अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है।

लेकिन जैसे ही सरकार जनता से त्याग और बचत की अपील करती है, राजनीति भी गर्म हो जाती है। विपक्ष का तर्क है कि यदि अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है तो जनता से ऐसी अपीलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वह इसे आर्थिक दबाव की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति बता रहा है। पेट्रोल-डीजल, गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच विपक्ष इस मुद्दे को 'जनता बनाम सत्ता' की बहस में बदलने की कोशिश कर रहा है।

हालाँकि इतिहास गवाह है कि संकट के समय जनता से संयम की अपील कोई नई बात नहीं है। लालबहादुर शास्त्री ने 1965 के खाद्यान्न संकट के समय देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का आह्वान किया था। उस दौर में लोगों ने इसे सरकारी आदेश नहीं बल्कि राष्ट्रधर्म माना। इसी प्रकार युद्धकाल में महिलाओं द्वारा अपने आभूषण तक राष्ट्रहित में दान करना भारतीय समाज की सामूहिक चेतना का उदाहरण रहा है।

जवाहर लाल नेहरु से लेकर इंदिरा गाँधी तक कई सरकारों ने विदेशी मुद्रा बचाने और आयात कम करने के लिए जनता से संयम की अपील की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी समय-समय पर सोने के बढ़ते आयात को अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बताया था। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को केवल राजनीतिक नजरिये से देखना पर्याप्त नहीं होगा।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि सरकार अपील क्यों कर रही है, बल्कि यह है कि क्या समाज इस संकट को अवसर में बदलने के लिए तैयार है?

यहीं पर महात्मा गाँधी का 'स्वदेशी' दर्शन फिर प्रासंगिक हो उठता है। गांधी जी के लिए स्वदेशी केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं था। वह आत्मनिर्भर भारत की ऐसी कल्पना थी जिसमें गांव मजबूत हों, स्थानीय उत्पादन बढ़े, कुटीर उद्योग फलें-फूलें और लोग आवश्यकताओं के अनुसार संयमित जीवन जीना सीखें। गांधी जी

समझते थे कि अत्यधिक उपभोग और विदेशी निर्भरता किसी भी राष्ट्र को भीतर से कमजोर करती है।

आज जब भारत तेल, सोना और विदेशी उत्पादों पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है, तब गांधी का 'सादा जीवन, उच्च विचार' केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति बन सकता है। यदि देश स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, कृषि आधारित रोजगार बढ़ें और दिखावे की संस्कृति से बाहर निकलकर स्वावलंबन की ओर कदम बढ़े, तो यही संकट भारत के लिए अवसर साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री द्वारा अपने काफिले को छोटा करना भी इसी प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दशकों से वीआईपी संस्कृति भारतीय लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती रही है। ऐसे समय में यदि सत्ता प्रतिष्ठान भी सादगी का संदेश देता है तो उसका नैतिक प्रभाव समाज पर पड़ता है। लेकिन विपक्ष की यह मांग भी उचित है कि सादगी केवल जनता तक सीमित न रहे—मंत्रियों के काफिले घटें, सरकारी फिजूलखर्ची कम हो, विदेश यात्राओं और राजनीतिक आयोजनों पर नियंत्रण दिखे। लोकतंत्र में त्याग का संदेश तभी प्रभावी होता है जब वह ऊपर से नीचे तक दिखाई दे।

दरअसल यह समय केवल आर्थिक नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का भी है। दुनिया युद्ध और अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत यदि उपभोगवादी मानसिकता से निकलकर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ता है, तो आने वाला दशक उसका हो सकता है।

सवाल केवल इतना नहीं कि हम कितना तेल बचाते हैं या कितना सोना कम खरीदते हैं। असली प्रश्न यह है कि क्या हम अपने गांव, अपने किसान, अपने कारीगर और अपने स्थानीय बाजार पर भरोसा करना सीख पाएंगे? यदि उत्तर 'हाँ' है, तो यह संकट भारत को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक आत्मनिर्भर, संगठित और शक्तिशाली बना सकता है।

युद्ध की आशंका, आर्थिक अनुशासन और वर्क फ्रॉम होम का विकल्प

वर्क फ्रॉम होम केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, इसका सामाजिक और मानसिक पक्ष भी है।

■ हर्षित पाण्डेय

प्रधानमंत्री की अपील केवल ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समय के प्रति तैयार रहने का संकेत भी है। युद्ध और वैश्विक संकटों के दौर में आर्थिक अनुशासन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और तकनीक आधारित कार्य प्रणाली भविष्य की आवश्यकता बनती जा रही है। वर्क फ्रॉम होम अब केवल महामारी का विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा बचत, आर्थिक स्थिरता और आधुनिक कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यदि सरकार, कॉर्पोरेट जगत और नागरिक मिलकर संतुलित और व्यावहारिक मॉडल विकसित करें, तो भारत संकट के समय भी विकास और स्थिरता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है।

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संभावित युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा बचत और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, अनावश्यक आयात पर नियंत्रण रखने और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील ने यह संकेत दिया है कि आने वाला समय केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक अनुशासन का भी हो सकता है।

इसी संदर्भ में 'वर्क फ्रॉम होम' यानी घर से काम करने की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। कोविड महामारी के दौरान दुनिया ने देखा कि तकनीक आधारित कार्यप्रणाली केवल आपातकालीन व्यवस्था नहीं, बल्कि एक प्रभावी आर्थिक मॉडल भी बन सकती है। आज जब वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति, परिवहन लागत और ऊर्जा संकट की आशंकाएं बढ़ रही हैं, तब वर्क फ्रॉम होम को केवल कर्मचारी सुविधा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है।

ईंधन बचत और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। ऐसे समय में यदि आईटी, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, मीडिया और अन्य डिजिटल कार्यक्षेत्रों में आंशिक रूप से वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाया जाए, तो लाखों लीटर ईंधन की बचत संभव है। इससे न केवल ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा, बल्कि विदेशी मुद्रा पर दबाव भी घट सकता है।

व्यावहारिक विकल्प के साथ सामाजिक और मानसिक प्रभाव

एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में कार्य करते हुए मेरा यह अनुभव है कि आज अधिकांश तकनीकी और प्रबंधन आधारित कार्य डिजिटल माध्यम से प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकते हैं। महामारी के दौरान कंपनियों ने पाया कि सही तकनीकी संरचना, साइबर सुरक्षा और परिणाम-आधारित कार्य संस्कृति के माध्यम से उत्पादकता बनाए रखी जा सकती है। कई कंपनियों ने कार्यालय खर्च, बिजली, परिवहन और संचालन लागत में उल्लेखनीय कमी भी दर्ज की। हालांकि, यह भी सच है कि हर क्षेत्र में पूर्ण वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और फील्ड आधारित कार्यों में भौतिक उपस्थिति आवश्यक रहती है। इसलिए भविष्य का मॉडल 'हाइब्रिड वर्क कल्चर' हो सकता है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार कार्यालय और घर दोनों से कार्य की व्यवस्था विकसित की जाए।

वर्क फ्रॉम होम केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, इसका सामाजिक और मानसिक पक्ष भी है। परिवार के साथ अधिक समय, यात्रा के तनाव में कमी और बेहतर जीवन संतुलन इसके सकारात्मक पहलू हैं।दूसरी ओर, लगातार घर से काम करने से सामाजिक अलगाव, टीम समन्वय में कमी और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसलिए कंपनियों को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी संतुलित कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी।

संकट में अवसर की तलाश

भारत के लिए यह समय केवल चुनौतियों का नहीं, बल्कि नए अवसरों का भी है। यदि देश डिजिटल इंफास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करता है, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े 'डिजिटल वर्कफोर्स हब' के रूप में उभर सकता है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी उच्च गुणवत्ता वाला कार्य संभव होगा, जिससे महानगरों पर दबाव कम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन मजबूत होगा।

बाजार में 'मॉर्निंग स्टार' - क्या यह स्थायी रिकवरी है या शॉर्ट-कवरिंग का जाल?

भारतीय इक्विटी बाजार का हालिया यू-टर्न, वैश्विक दबाव और निवेशकों के लिए रोडमैप

बाजार ने पलटी बाजी

समीर दुबे
एडिटर छत्तीसगढ़
K News India

लगातार चार सत्रों की गिरावट और चौतरफा बिकवाली के बाद, भारतीय शेयर बाजार ने मई के मध्य में एक बार फिर सबको चौंकाते हुए शानदार वापसी की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निरंतर निकासी और एशियाई मुद्राओं में रुपये के सर्वकालिक निचले स्तर (95.96 प्रति डॉलर) पर खिसकने के बावजूद घरेलू बाजार मजबूती से डटा हुआ है।

गुरुवार के कारोबारी सत्र में BSE सेंसेक्स 789.74 अंक (1.06%) की छलांग लगाकर 75,398.72 पर बंद हुआ, जबकि हस्थ निफ्टी 50 ने 277 अंकों की बढ़त के साथ 23,689.60 का स्तर हासिल कर लिया। इस रिकवरी ने तकनीकी चार्ट पर एक मजबूत 'बुलिश कैंडल' बनाई है, जिसे विशेषज्ञ 'मॉर्निंग डोजी स्टार' पैटर्न मान रहे हैं।

सेक्टोरल रोटेशनः फार्मा और मेटल चमके, आईटी पर ग्रहण

बाजार की इस तेजी में चुनिंदा सेक्टर्स ने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि कुछ पारंपरिक हैवीवेट्स में बिकवाली जारी रही-

1.) **फार्मा और हेल्थकेयर** (Top Gainers): सिप्ला (Cipla) और जायडस (Zydus) के बेहतरीन Qy नतीजों के दम पर यह इंडेक्स 2.5% से अधिक उछला।

2.) **मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर**-अमेरिकी-चीन व्यापार वार्ताओं (Trump-Xi Summit) में सकारात्मक संकेतों से वेदांता और अडाणी एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स में भारी वॉल्यूम देखा गया।

3.) **आईटी सेक्टर (The Only Loser):** ओपनएआई (Open AI) द्वारा उद्यम एआई (Enterprise AI) क्षेत्र में 4 बिलियन के नए निवेश की घोषणा के बाद भारतीय आईटी कंपनियों (Infosys, HCL Tech) के पारंपरिक मॉडल पर दबाव दिखा और पूरा इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ।

बाजार को दिशा देने वाले 3 बड़े फैक्टर्स

मई 2026 का रिपोर्ट कार्ड

मुख्य सूचकांक	क्लोजिंग लेवल	तात्कालिक सपोर्ट	तात्कालिक रेजिस्टेंस
निफ्टी 50	23,689.60	23,600	23,800
बैंक निफ्टी	54,128.95	53,900	54,400
सेंसक्स	75,398.72	74,800	75,900

डेटा स्रोत: *NSE India Live Data*

* **विदेशी बॉन्ड पर टैक्स कटौती की अफवाहें** -बाजार में सबसे बड़ी तेजी सरकारी हलकों से आई उन खबरों के बाद दिखी, जिनमें विदेशी निवेशकों के लिए बॉन्ड टैक्स में कटौती की संभावना जताई गई है ताकि रुपये की कमजोरी को थामा जा सके।
* **कच्चे तेल का उबाल**- ब्रेंट क्रूड अभी भी प्रति बैरल उच्च स्तर पर बना हुआ है, जो भारत जैसे आयातक देश के लिए राजकोषीय घाटे की चिंता बढ़ाता है।
* **शॉर्ट कवरिंग**-वीकली एक्सपायरी के दिन निचले स्तरों पर आक्रामक शॉर्ट कवरिंग ने सूचकांकों को दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक ऊपर धकेल दिया।

निवेशकों के लिए क्या है रणनीति?

मासिक निवेशकों के लिए दलाल स्ट्रीट के दिग्गजों की स्पष्ट सलाह है कि 'जल्दबाजी में आक्रामक न हों।' बाजार अभी पूरी तरह से अनिश्चितता के दौर से बाहर नहीं निकला है।

* **लार्ज-कैप सेफ्टी नेट**- मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज-कैप स्टॉक्स (विशेषकर बैंकिंग और अर्निंग विजिबिलिटी वाले सेक्टर्स) में पैसा लगाना अधिक सुरक्षित है।
* **स्टॉप-लॉस का सख्त नियम**-यदि आप स्विंग या पोजीशनल ट्रेडर हैं, तो निफ्टी के 23,600 के स्तर को बेहद कड़ा स्टॉप-लॉस मानें।
* **एसआईपी (SIP) अप्रोच**- देश की मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए हर गिरावट को क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी बढ़ाने के मौके के रूप में इस्तेमाल करें।

वैश्विक चुनौतियां बनाम घरेलू ताकत - त्रिकोणीय मुकाबला

क्या खत्म हो रही है क्षेत्रीय राजनीति की ताकत?

■ नरेन्द्र पाण्डेय

बंगाल और असम में बीजेपी की यह प्रचंड जीत 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है. इन नतीजो का सीधा असर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर पड़ना तय है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद्य दुर्ग को ढहाने के बाद 'भगवा' खेमे में जो उत्साह है, उसकी गूंज अब लखनऊ के सियासी गलियारों तक भी सुनाई दे रही है?

पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु , केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणाम सोमवार को सामने आ गए. इन परिणामों ने भारतीय राजनीति के भविष्य पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डीएमके) और अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) की पराजय तथा केरल में वाम मोर्चे का लगभग सफाया हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्चस्व तेजी से कम हो रहा है. बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके बहुत ही मजबूत पार्टियां हैं पर जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की हालत भी बेहाल दिखाई दे रही है. यह महज संयोग नहीं, बल्कि पिछले एक दशक से चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है. भारत अब अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर द्विदलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. 2014 के बाद से केंद्र में मजबूत बहुमत वाली सरकार ने नीतियों को इस तरह केंद्रीकृत किया कि राज्य के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों में विलीन हो गए. जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, कृषि कानूनों का विवाद, सीएए-एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन की बहस और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया. नतीजतन, क्षेत्रीय दल जो स्थानीय मुद्दों पानी, बिजली, रोजगार, भाषा और संस्कृति पर आधारित थे, अब राष्ट्रीय दलों की छाया में सिकुड़ते जा रहे हैं. जहां पहले तमिलनाडु में डीएमके-एआईएडीएमके, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी-जद(यू) और उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा जैसे गठबंधन राज्य की राजनीति तय करते थे, वहां आज राष्ट्रीय दल ही इन राज्यों का भविष्य तय कर रहे हैं.इस बदलाव को शुभ मानने वालों का तर्क सरल है. द्विदलीय व्यवस्था स्थिरता लाती है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो दलों की व्यवस्था कई मायनों में बेहतर होती है. अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव

और लेबर पार्टी के बीच सत्ता हस्तांतरण सुचारू होता है. नीतियां निरंतरता रखती हैं. भ्रष्टाचार कम होता है क्योंकि क्षेत्रीय दल अक्सर परिवारवाद, जातिवाद और स्थानीय माफिया से जुड़े दिखते हैं. इसके विपरीत द्विदलीय मॉडल में मतदाता स्पष्ट विकल्प चुन पाते हैं.

बंगाल और असम में बीजेपी की यह प्रचंड जीत 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है. इन नतीजो का सीधा असर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर पड़ना तय है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद्य दुर्ग को ढहाने के बाद 'भगवा' खेमे में जो उत्साह है, उसकी गूंज अब लखनऊ के सियासी गलियारों तक भी सुनाई दे रही है? यह 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक 'लॉन्चपैड' तैयार कर दिया है. बीजेपी ने जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी को मात दी है, उससे अखिलेश यादव के चैलेंज से निपटने में नई ऊर्जा मिलेगी. उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था. बीजेपी ने दो साल में कमबैक किया है. ऐसे में बंगाल में ममता की हार विपक्ष के लिए बड़ा झटका है तो बीजेपी के लिए यूपी में 'बुस्टर डोज' की तरह है, जो सपा-कांग्रेस के लिए किसी सियासी टेंशन से कम नहीं है? बंगाल में मिली सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ अब 2027 के लिए और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे. बंगाल के नतीजों ने साबित कर दिया कि बीजेपी का 'हिंदुत्व कार्ड' ने विपक्ष के सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर सेंधमारी ने 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाले नैरेटिव को धार देने के लिए 'धार्मिक ध्रुवीकरण' की बिसात बिछाई. इसका नतीजा था कि 30 फीसदी मुस्लिम बंगाल में होने के बाद भी बीजेपी जीतने में सफल रही है. बीजेपी अब 'सामाजिक न्याय' के जवाब में 'सांस्कृतिक एकीकरण' को और मजबूती से पेश करेगी. सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो अक्सर ममता बनर्जी को अपनी 'बड़ी बहन' और आदर्श मानते रहे हैं, उनके लिए बंगाल में टीएमसी की हार यह बड़ा झटका है.

लेकिन आज जब क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं तो संघीय भावना भी कमजोर हो रही है. दिल्ली में केंद्र सरकार के फैसले अब राज्यों की विधानसभाओं को आसानी से ओवरराइड कर रहे हैं. वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, गवर्नर की भूमिका और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल आदि ने केंद्र की ताकत को बढ़ाया है. दूसरी ओर, क्षेत्रीय दलों की गिरावट के पीछे उनकी अपनी कमियां भी हैं. परिवारवाद, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों से ऊपर नहीं उठ पाना इनकी सबसे बड़ी विफलता रही है. मतदाता अब विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, न कि सिर्फ जाति या क्षेत्रीय भावना को आधार बना रहे हैं. इसलिए राष्ट्रीय दलों की अपील बढ़ रही है.

सवाल यह है कि क्या द्विदलीय व्यवस्था भारत की बहुलता को बरकरार रख पाएगी? अमेरिका और ब्रिटेन एकराष्ट्रीय, एकभाषी और अपेक्षाकृत समरूप समाज हैं. भारत में ऐसा नहीं है. यहां अगर केवल दो राष्ट्रीय दल रह गए तो असम, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर या पूर्वोत्तर के स्थानीय मुद्दे कौन उठाएगा? क्या एक राष्ट्रीय पार्टी बंगाली, तमिल, मराठी या पंजाबी अस्मिता को पूरी तरह समेट पाएगी? इतिहास गवाह है कि जब केंद्र बहुत मजबूत होता है तो क्षेत्रीय असंतोष अलगाववाद का रूप ले लेता है. संविधान निर्माताओं ने जो अनेकता में एकता का सपना देखा था, वह क्षेत्रीय दलों के फलने-फूलने पर टिका था. आज जब हम द्विदलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं, बल्कि विविधता की रक्षा का भी नाम है. अगर क्षेत्रीय दल पूरी तरह लुप्त हो गए तो भारतीय संघीयता का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा. समय आ गया है कि हम इस ट्रेंड पर गंभीरता से विचार करें.

बदलती भाजपा

संगठन, सत्ता में नए समीकरणों की आहट

■ नरेन्द्र पाण्डेय

राजनीति में हर बड़ी जीत केवल एक राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। चुनाव परिणाम सत्ता बदलने से अधिक, संगठन की दिशा, नेतृत्व की प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति को भी तय करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नए आत्मविश्वास को जन्म दिया है। यह आत्मविश्वास केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि राज्यों की राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं दिखाई देता।

भाजपा की राजनीति हमेशा संगठन आधारित मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के भीतर 'परफॉर्मेंस आधारित प्रमोशन' की संस्कृति और अधिक मजबूत हुई है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में उपमुख्यमंत्री विजय शर्माजी से उभरते हुए ऐसे चेहरे बन गए हैं, जिन्हें केवल सरकार के मंत्री के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के बड़े राजनीतिक सेतु के रूप में भी देखा जा रहा है।

विजय शर्मा की राजनीति की विशेषता यह है कि वे संगठन और सत्ता—दोनों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता रखते हैं। भाजपा में ऐसे नेताओं की हमेशा आवश्यकता रहती है जो केवल प्रशासनिक निर्णय लेने वाले न हों, बल्कि संगठनात्मक संवेदनाओं को भी समझते हों। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी निकटता और राज्यों के नेताओं के साथ सहज संबंध उन्हें पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। ऐसे समय में जब भाजपा राज्यों में अपने नेतृत्व का पुनर्संतुलन कर रही है, विजय शर्मा जैसे नेता 'ब्रिज पॉलिटिक्स' के प्रतिनिधि बनकर उभर सकते हैं।

दूसरी ओर पवन सायलंबे समय से संगठन मंत्री के रूप में स्थिरता और अनुशासन का प्रतीक रहे हैं। भाजपा में संगठन मंत्री का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक माना जाता है। यह वही भूमिका होती है जो कार्यकर्ता, संगठन और नेतृत्व के बीच अदृश्य सूत्रधार का काम करती है। वर्षों तक संगठन में सक्रिय रहने वाले नेताओं को भाजपा समय-समय पर नई जिम्मेदारियां देती रही है। ऐसे में यह चर्चा स्वाभाविक है कि पवन साय को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका मिल सकती है।

यदि ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठनात्मक पुनर्संरचना की प्रक्रिया शुरू होगी। यही वह बिंदु है जहां विजय शर्मा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। भाजपा आज केवल चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि वह सामाजिक विस्तार और नए वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल जैसे कठिन राज्य में मिली सफलता ने पार्टी को यह विश्वास दिया है कि राजनीतिक रूप

से असंभव दिखने वाले क्षेत्रों में भी संगठन खड़ा किया जा सकता है।

इस मनोवैज्ञानिक बढ़त का असर राज्यों में भी दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय नए सामाजिक समीकरणों को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसके लिए संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर चलना होगा। यही कारण है कि पवन साय और विजय शर्मा दोनों का राजनीतिक कद समानांतर रूप से बढ़ता दिखाई दे रहा है।

हालांकि भाजपा में निर्णय केवल व्यक्तिगत समीकरणों के आधार पर नहीं होते। पार्टी की कार्यप्रणाली व्यापक रणनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित रहती है। इसलिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि कोई परिवर्तन निश्चित है। लेकिन इतना स्पष्ट जरूर है कि पांच राज्यों के चुनाव परिणामों ने छत्तीसगढ़ भाजपा के भीतर नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।

इसी बीच भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक ने संगठनात्मक ऊर्जा से अधिक अंदरूनी असंतोष को चर्चा का विषय बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नई कार्यसमिति में 23 विधायकों को स्थान नहीं दिए जाने से यह सवाल उठने लगा कि क्या भाजपा अब संगठन के भीतर नई शक्ति-संरचना तैयार कर रही है, या फिर यह केवल संतुलन साधने का प्रयास है।

भाजपा की परंपरा रही है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विशेषकर विधायकों, को प्रदेश कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में स्थान मिलता रहा है। यही कारण है कि इस बार कई सक्रिय और वरिष्ठ विधायकों के बाहर रहने को सामान्य संगठनात्मक फेरबदल नहीं माना जा रहा। जब 54 विधायकों वाली सरकार में केवल चुनिंदा चेहरों को मंच मिले और बाकी को बैठक से दूर रखा जाए, तो उसका संदेश केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन जाता है।

यह विवाद इसलिए भी गहरा हुआ क्योंकि जिन नेताओं को बाहर रखा गया उनमें संगठन और जनाधार दोनों स्तरों पर प्रभाव रखने वाले चेहरे शामिल हैं। भाजपा लंबे समय तक 'सामूहिक नेतृत्व' की पार्टी कही जाती रही है। लेकिन अब यह धारणा मजबूत होने लगी है कि पार्टी के भीतर 'विश्वासपात्र चेहरों' और 'निकटता की राजनीति' को प्राथमिकता मिलने लगी है।

कोर कमेटी से कई वरिष्ठ नेताओं को बाहर किया जाना भी सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। रमन सिंह, रामविचार नेताम , बृजमोहन अग्रवालऔर रेणुका सिंहजैसे अनुभवी नेताओं की जगह नए चेहरों को आगे लाना भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है जिसमें संगठन भविष्य के नेतृत्व को तैयार करना चाहता है।

लेकिन राजनीति केवल संगठनात्मक गणित से संचालित नहीं होती। वह सम्मान, सहभागिता और संवाद की भावना से भी चलती है। यदि विधायक स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगें तो यह असंतोष भविष्य में गुटीय राजनीति को जन्म दे सकता है। भाजपा का कैडर मॉडल हमेशा इस विश्वास पर टिका रहा कि मेहनत करने वाले कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को समान अवसर मिलेगा। यदि यह भरोसा कमजोर पड़ता है तो उसका असर संगठनात्मक मनोबल पर भी दिखाई देगा।

सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिन विधायकों को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य माना गया, वही अपने राज्य की कार्यसमिति में शामिल नहीं किए गए। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या संगठनात्मक निर्णय अब योग्यता से अधिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर होने लगे हैं।

दबी जुबान में उठ रहे गुटबाजी के आरोप यह संकेत देते हैं कि भाजपा के भीतर भी अब वही प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी हैं जिनकी आलोचना वह लंबे समय तक अन्य दलों में करती रही है। सत्ता और संगठन के बीच संतुलन भाजपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती रही है, लेकिन यदि यह संतुलन कमजोर होता है तो उसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं।

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान हजारों वाहनों का कार्यालय पहुंचना भी चर्चा का विषय बना। एक ओर नरेन्द्र मोदी ईंधन संकट, संयमित संसाधन उपयोग और सादगी की बात करते हैं, दूसरी ओर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की संस्कृति अब भी पुराने ढर्रे पर चलती दिखाई देती है। यह केवल व्यवस्थागत सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति का भी प्रश्न है।

आज भारतीय राजनीति एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है। विचारधारा और संगठनात्मक प्रतिबद्धता की जगह अब ब्रांडिंग, इमेज मैनेजमेंट और केंद्रीकृत नेतृत्व अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं। भाजपा भी इस परिवर्तन से पूरी तरह अछूती नहीं दिखती।

यह पूरा घटनाक्रम केवल 23 विधायकों के बाहर रहने का मामला नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या भाजपा अब 'संगठन आधारित पार्टी' से 'केंद्रित नेतृत्व वाली पार्टी' की ओर बढ़ रही है? क्या निर्णय प्रक्रिया सीमित समूहों तक सिमटती जा रही है? और क्या भविष्य की राजनीति में संगठनात्मक संवाद की जगह रणनीतिक नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा?

यदि ऐसा है, तो यह बदलाव केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में यह भाजपा की नई राजनीतिक कार्यशैली का मॉडल भी बन सकता है।

अंततः राजनीति संभावनाओं का खेल है। और इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ी संभावना यही दिखाई देती है कि संगठन और सत्ता—दोनों में नए चेहरे, नई भूमिकाएं और नए समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं।

सौम्यता में सख्ती विष्णुदेव साय की प्रशासनिक शैली

जशपुर के ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचना और फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद तक आना केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि धैर्य, संगठनात्मक निष्ठा और जनसंपर्क का परिणाम है। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। साय का व्यक्तित्व जितना शांत दिखाई देता है, प्रशासनिक मामलों में उनकी कार्यशैली उतनी ही स्पष्ट और अनुशासित मानी जा रही है।

■ लाईफ वर्सिटी विशेष

छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता के कारण नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, कार्यशैली और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के कारण पहचान बनाते हैं। विष्णुदेव साय उन्हीं नेताओं में से एक हैं। शांत स्वभाव, सहज मुस्कान और आदिवासी अंचल की मिट्टी से जुड़ी सादगी—यह उनका बाहरी व्यक्तित्व है। लेकिन प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक निर्णयों में वही व्यक्ति बेहद कठोर और स्पष्ट दिखाई देता है। यही संतुलन आज उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में अलग पहचान देता है।

विष्णुदेव साय का व्यक्तित्व न तो आक्रामक भाषणों वाले नेता की हैं और न ही टकराव की राजनीति के प्रतीक। उनकी पहचान एक सहज, सरल और जमीन से जुड़े जननेता की रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके प्रशासनिक फैसलों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी सौम्यता को कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। उनकी कार्यशैली में एक ओर विनम्रता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर प्रशासनिक अनुशासन और निर्णय क्षमता की सख्ती भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। यही संतुलन आज उनकी राजनीतिक पहचान को मजबूत बना रहा है।

जशपुर के ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचना और फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद तक आना केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि धैर्य, संगठनात्मक निष्ठा और जनसंपर्क का परिणाम है। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। साय का व्यक्तित्व जितना शांत दिखाई देता है, प्रशासनिक मामलों में उनकी कार्यशैली उतनी ही स्पष्ट और अनुशासित मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने शासन व्यवस्था में जवाबदेही और त्वरित निर्णय की संस्कृति पर जोर दिया। उनकी राजनीतिक शैली टकराव की राजनीति से अलग दिखाई देती है। वे संवाद, संगठन और प्रशासनिक नियंत्रण—तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वे राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय जनभावनाओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में उभरे हैं।

'मोदी की गारंटी' को जमीन पर उतारने की बात हो या प्रशासनिक कसावट लाने की—साय सरकार ने शुरुआती दौर से ही परिणाम आधारित शासन शैली पर जोर दिया है। यही कारण है कि अधिकारियों की जवाबदेही और योजनाओं की मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी गई। विष्णुदेव साय ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासनिक मशीनरी को संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को अब सामान्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अधिकारियों को लगातार यह निर्देश दिया जा रहा है कि जनता से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनकी कार्यशैली में यह दिखाई देता है कि वे शासन व्यवस्था में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं। कई विभागों में कार्यप्रणाली की समीक्षा और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया ने प्रशासनिक हलकों में सक्रियता बढ़ाई है।

कृषि और किसान कल्याण-भरोसे की राजनीति

साय सरकार ने शुरुआत से ही किसानों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया। धान खरीदी, बकाया बोनस और किसानों को आर्थिक राहत से जुड़े फैसलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश दिया। सरकार ने समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। कृषि

विभाग द्वारा आधुनिक खेती, सिंचाई और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास : 'महतारी वंदन योजना' से सामाजिक संदेश

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की

गई 'महतारी वंदन योजना' सरकार की प्रमुख योजनाओं में उभरी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण, मातृ स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी है।

गृह विभाग-नशे और अपराध के खिलाफ सख्ती

साय सरकार की प्रशासनिक सख्ती सबसे अधिक गृह विभाग की कार्यप्रणाली में दिखाई दी। राज्य में बढ़ती नशाखोरी और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन को व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कई जिलों में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। सरकार ने इसे केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा मुद्दा माना।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के संतुलन पर भी सरकार ने जोर दिया। सुरक्षा बलों की सक्रियता के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास : गांवों तक प्रशासन

साय सरकार ने ग्रामीण प्रशासन को अधिक सक्रिय बनाने पर

विशेष ध्यान दिया। सुशासन तिहार जैसे अभियानों के माध्यम से गांव-गांव जाकर समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। पंचायत विभाग के जरिए ग्रामीण सड़क, जल सुविधा और रोजगार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का प्रयास हुआ। शासन की यह शैली यह संकेत देती है कि सरकार प्रशासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है।

स्वास्थ्य विभागः सुविधाओं के विस्तार की कोशिश

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार ने कई कदम उठाए। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने, जांच सुविधाएं बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग को भी प्राथमिकता दी गई।

शिक्षा और युवा : कौशल एवं रोजगार पर फोकस

शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देने की कोशिश हुई। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगारपरक योजनाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति दिखाई दी। सरकार यह संदेश देने का प्रयास करती दिख रही है कि विकास केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि युवाओं को अवसर देने से संभव होगा।

उद्योग और निवेश : विकास की नई दिशा

साय सरकार ने उद्योग निवेश और रोजगार सृजन को भी

प्राथमिकता में रखा। राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ में उद्योग और स्थानीय रोजगार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सरकार गंभीरता से लेने का संकेत देती दिखाई देती है।

संतुलित नेतृत्व की उभरती छवि

विष्णुदेव साय की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह दिखाई देती है कि वे संवाद और अनुशासन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में आक्रामकता कम, लेकिन प्रशासनिक स्पष्टता अधिक दिखाई देती है। यही कारण है कि वे एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो शांत स्वभाव के बावजूद शासन में सख्ती और जवाबदेही स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं

हालांकि किसी भी सरकार की अंतिम सफलता योजनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव और जमीनी परिणामों से तय होती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि साय सरकार की योजनाएं और प्रशासनिक कसावट छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में कितना स्थायी परिवर्तन ला पाती हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में विष्णुदेव साय एक ऐसे नेता के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं, जो सौम्यता और सख्ती—दोनों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति में संवाद की विनम्रता है, लेकिन प्रशासनिक निर्णयों में स्पष्टता भी दिखाई देती है। यही संतुलन आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति साबित हो सकता है।

जनविश्वास और जवाबदेही के नए अध्याय

सुशासन तिहार

इस अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना, शिकायतों का त्वरित निराकरण करना और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों से संवाद, योजनाओं की समीक्षा और मौके पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया ने इस अभियान को सामान्य सरकारी कार्यक्रमों से अलग पहचान दी है। खास बात यह रही कि कई स्थानों पर मुख्यमंत्री स्वयं भी औचक निरीक्षण और जनसंवाद कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिससे प्रशासनिक अमले में सक्रियता दिखाई दी।

■ **लाईफ वर्सिटी विशेष**

छत्तीसगढ़ में आयोजित 'सुशासन तिहार' अब केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में बदलाव की एक व्यापक पहल के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्रीविष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के माध्यम से शासन गांव-गांव तक पहुंचकर न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और किसानों के जीवन में भी नई उम्मीदें जगा रहा है।

इस अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना, शिकायतों का त्वरित निराकरण करना और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों से संवाद, योजनाओं की समीक्षा और मौके पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया ने इस अभियान को सामान्य सरकारी कार्यक्रमों से अलग पहचान दी है। खास बात यह रही कि कई स्थानों पर मुख्यमंत्री स्वयं भी औचक निरीक्षण और जनसंवाद कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिससे प्रशासनिक अमले में सक्रियता दिखाई दी।

राज्य के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए यह अभियान खुशियों की सौगात लेकर आया है। कई गांवों में तालाबों के जीर्णोद्धार, मत्स्य पालन योजनाओं और सरकारी सहायता के विस्तार से ग्रामीणों की आय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ी हैं। वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अब स्थानीय स्तर पर योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों मिल रहे हैं। इससे वर्षों से उपेक्षित समुदायों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

'सुशासन तिहार' के दौरान स्थापित ग्रामीण सचिवालय अब गांवों में त्वरित समाधान का केंद्र बनते जा रहे हैं। ग्रामीणों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। राशन कार्ड, पेंशन, राजस्व प्रकरण, बिजली, पेयजल और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का निराकरण गांव स्तर पर ही किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।सरकार का दावा है कि 'सुशासन तिहार' का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को यह विश्वास दिलाना है कि शासन केवल राजधानी तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अभियान का सबसे प्रभावशाली पक्ष महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को माना जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं अब आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो रही हैं। कई क्षेत्रों में महिलाओं ने छोटे उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और जल संरक्षण कार्यों में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है।विशेष रूप सेरायगढ़जिले में महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण के प्रयासों ने ग्रामीण विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत की है। गांवों में जल संरचनाओं के निर्माण, तालाब संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी से खेती और पशुपालन को मजबूती मिली है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इन योजनाओं को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप कई गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

दूसरी ओर 'सुशासन तिहार' किसानों के लिए भी राहत और समाधान का माध्यम बनता जा रहा है। किसान अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने रख पा रहे हैं। फसल, सिंचाई, खाद-बीज, बिजली और मुआवजा संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक वातावरण बनाया है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और कृषि व्यवस्था को मजबूत आधार प्राप्त हो।

वनांचल क्षेत्रों की महिलाओं तक स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान पहुंचना भी इस पहल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से महिलाओं की जांच, पोषण संबंधी परामर्श और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद मिली है।

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो 'सुशासन तिहार' सरकार और जनता के बीच संवाद का नया माध्यम बनता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि शासन की वास्तविक सफलता तभी है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही कारण है कि यह अभियान प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायलगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सरकार पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के आधार पर कार्य करेगी। विभिन्न सभाओं में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं को केवल फाइलों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की वास्तविक परीक्षा गांवों और आम लोगों के बीच होती है। हालांकि विपक्ष इस अभियान को लेकर सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 'सुशासन तिहार' के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चला रही है, जबकि जमीनी स्तर पर बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और स्थानीय मुद्दे अब भी पूरी तरह हल नहीं हो पाए हैं। विपक्ष का कहना है कि केवल शिविर और घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्थायी समाधान और निरंतर निगरानी आवश्यक है।

इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही प्रतिक्रियाएं यह संकेत देती हैं कि लोगों में अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने की उत्सुकता बढ़ी है। कई गांवों में वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू होने से लोगों में सकारात्मक संदेश गया है। यही कारण है कि 'सुशासन तिहार' को राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं के प्रमुख अभियान के रूप में प्रस्तुत कर रही है।यदि यह अभियान केवल आयोजन तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधार में बदलता है, तो यह छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में बदलती यह तस्वीर संकेत दे रही है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही प्रकार जमीन तक पहुंचता रहा, तो 'सुशासन तिहार' राज्य के विकास मॉडल की नई पहचान बन सकता है।आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता को किए गए वादों और घोषणाओं का वास्तविक लाभ कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ मिलता है।

आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव पंचायती राज

रायपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित विमतारा भवन में अखिल भारतीय पंचायत परिषद की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई द्वारा प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल एक औपचारिक कार्यक्रम था, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मा — पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और सुदृढ़ करने का एक प्रेरणादायक मंच भी बना।

इस भव्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बृजमोहन अग्रवाल (लोकसभा सांसद, रायपुर) उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रविन्द्रनाथ तिवारी (उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद एवं सदस्य , रास्ट्रीय सड़कसुरक्षा परिषद) तथा विशेष अतिथि के रूप में अमरजीत सिंह छाबड़ा (अध्यक्ष, छग अल्पसंख्यक आयोग,राज्य मंत्री दर्जा) की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में देश के लगभग छह राज्यों से आए अखिल भारतीय पंचायत परिषद के पदाधिकारियों सहित प्रदेश के विभिन्न जिलो से आये प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और ग्रामीण विकास के साझा संकल्प का प्रतीक बन गया।

गांधी, लोहिया और अटल के विचारों का संगम

कार्यक्रम में परिषद के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रूद्रभानु द्वारा बताया गया कि बलवंत राय मेहता ने लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने की जो नींव रखी, उसी के आधार पर आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देशभर में लागू है। बलवंत राय मेहता न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, बल्कि उन्होंने ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मजबूती दी। वे गुजरात के मुख्यमंत्री (1963-1965) भी रहे, जहां उन्होंने प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में बनी समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की संरचना विकसित हुई, जिसे 73वें संविधान संशोधन (1992) के जरिए संवैधानिक दर्जा मिला।

पंचायती राज व्यवस्था को केवल प्रशासनिक ढांचा मानना इसकी आत्मा को सीमित करना होगा। यह व्यवस्था उन महान विचारों का संगम है, जिन्होंने भारत के ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज — जहाँ हर गाँव आत्मनिर्भर और स्वशासी हो . डॉ. राम मनोहर लोहिया का समतामूलक समाज — जहाँ समानता और न्याय हो . अटल बिहारी वाजपेयी का आत्मनिर्भर गाँव — जो राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बने इन विचारों का जीवंत रूप है पंचायती राज, जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाता है। डॉ. रूद्र भानु ने जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में पंचायतों को डिजिटल और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ही देश के समग्र विकास की कुंजी होगा।

मुक्य वक्ता के तौर पर रायपुर लोकसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री छग शासन बृजमोहन अग्रवाल ने पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकांश जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों और पंचायतों को मिले संवैधानिक अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण विकास कार्य केवल सड़क, नाली और पुलिया तक ही सीमित रह जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 29 विषयों से सशक्त पंचायत और ग्रामसभा विकास का मजबूत आधार हैं। यदि पंचायत प्रतिनिधि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के साथ समन्वय बनाकर काम करें, तो उन्हें सांसद या विधायक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार, 'गांव स्तर पर ही ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो न केवल विकास को गति दें, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर, सशक्त और आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती हैं।' उनके इस बयान ने कार्यक्रम में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकारों के प्रति जागरूक होने और स्थानीय स्तर पर विकास की नई संभावनाओं पर काम करने का संदेश दिया।

पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला वह सशक्त माध्यम है, जो हर गाँव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ता है। आज आवश्यकता है कि हम इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करें, उसमें पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा दें, ताकि हर गाँव आत्मनिर्भर बने और हर नागरिक सशक्त। क्योंकि सच यही है– 'मजबूत गाँव ही मजबूत भारत की पहचान हैं।'

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रवीन्द्रनाथ तिवारी ने ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि यदि सरकार कानून को लेकर पूरी तरह ईमानदार है, तो ग्रामसभा को उसके पूर्ण अधिकार अब तक क्यों नहीं दिए गए। तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की बात तो की जाती है, लेकिन व्यवहार में ग्रामसभा आज भी सीमित अधिकारों में बंधी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र वास्तव में गांव तक पहुंचा है, या फिर यह केवल कागजों और सरकारी दस्तावेजों तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और निर्णय लेने की शक्ति को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामसभाएं आज भी कई मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहीं।

तिवारी ने यह भी रेखांकित किया कि जब तक ग्रामसभा को वित्तीय, प्रशासनिक और निर्णयात्मक अधिकार पूरी तरह नहीं मिलते, तब तक ग्रामीण विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कहा कि योजनाओं की वास्तविक जरूरत और प्राथमिकता गांव के लोग ही बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्हें ही निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि पंचायतों और विशेष रूप से ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया बन सके।

पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला वह सशक्त माध्यम है, जो हर गाँव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ता है। आज आवश्यकता है कि हम इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करें, उसमें पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा दें,

सम्मेलन का उद्देश्य

राजस्थान से आये पराशर ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र की नींव को गहराई देती है। यह केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनभागीदारी का सशक्त माध्यम है। गाँवों में पंचायतों के माध्यम से— स्वच्छता अभियान को गति मिलती है, स्वरोजगार के अवसर सृजित होते हैं ,शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं का स्थानीय प्रबंधन होता है , योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनता है,यह व्यवस्था ग्रामीण नागरिकों को निर्णय लेने का अधिकार देती है, जिससे वे अपने विकास के स्वयं निर्माता बनते हैं। उन्होंने कहा कि 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को दिए गए 29 विषयों—कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सड़क और जल प्रबंधन—को ग्राम स्वराज की असली ताकत बताया। कहा गया कि यही व्यवस्था महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करती है।

छत्तीसगढ़ निर्माण के भागीरथी एवं छग राज्य पंचायत परिषद के सलाहकार डॉ उदयभान सिंह चौहान ने कहा - इस प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्न राज्यों के अनुभवों का आदान-प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि— 'आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हमारे गाँव आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे।' आयोजन समिति ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण विकास की दिशा में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि एक सतत अभियान की शुरुआत है— एक ऐसा अभियान, जो गाँवों को सशक्त बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम के समापन के बाद नवगठित छग राज्य पंचायत परिषद ने अपनी वर्तमान संगठनात्मक स्थिति और कार्यप्रणाली पर गंभीर समीक्षा की। इस दौरान संगठन की जमीनी सक्रियता, संवाद व्यवस्था और नेतृत्व की प्रभावशीलता को लेकर कई अहम सवाल सामने आए।AIPP के जनरल सेक्रेटरी डॉ. रुद्र भानु ने साफ शब्दों में कहा कि 'संगठन केवल बड़े कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, मजबूत संरचना और स्पष्ट रणनीति से सशक्त होते हैं। कार्यक्रम प्रेरणा देते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य उसके बाद प्रारंभ होता है।'

समीक्षा बैठक में सामने आए प्रमुख मुद्दों में— पदाधिकारियों में जिम्मेदारियों की स्पष्टता , प्रभावी कम्युनिकेशन सिस्टम , निचले स्तर तक पहुँचना एवं पदाधिकारियों के बीच मजबूत समन्वय . डॉ. भानु ने स्पष्ट किया कि संगठन विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर चलता है, जहां व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक निर्णय सर्वोपरि होते हैं। संगठन को कार्यक्रम आधारित मॉडल से निकालकर सिस्टम आधारित ढांचे में लाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना घोषित की गई है . परिषद ने सदस्यता अभियान तेज करने, पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ने और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का भी फैसला लिया है। साथ ही 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था की समझ को मजबूत करने के लिए वैचारिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत परिषद ने संगठनात्मक विस्तार और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जनरल सेक्रेटरी, डॉ. रुद्र भानु द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है।

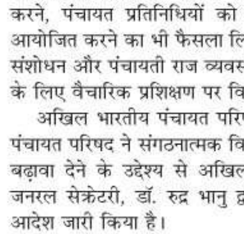

इस आदेश के तहत 'लाइफ वर्सिटी' के संपादक एवं परिषद के प्रवक्ता नरेंद्र कुमार पाण्डेय को मीडिया से जुड़े अहम दायित्व सौंपे गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, 'पंचायत संदेश छत्तीसगढ़' (मुख्य पत्रिका) के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही परिषद के आधिकारिक YouTube चैनल की स्थापना, संचालन और विकास का कार्य भी उनके जिम्मे दिया गया है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक ये व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जातीं, तब तक नरेन्द्र कुमार पाण्डेय अपनी पत्रिका 'लाइफ वर्सिटी' और SCG NEWS, YouTube चैनल के माध्यम से पंचायत परिषद, महात्मा गांधी और बलवंत राय मेहता के विचारों के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक अधिकारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करते रहेंगे।

क्या जड़ों से कट रही ग्राम व्यवस्था? ग्राम स्वराज की नई चुनौती

डॉ उदयभान सिंह चौहान
(सामाजिक चिन्तक-विचारक)

भारत को गांवों का देश कहा जाता है। आज भी देश की बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है, लेकिन विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में वही गांव सबसे पीछे दिखाई देने लगे हैं। कभी आत्मनिर्भर और सामुदायिक जीवन का केंद्र रहे गांव आज पलायन, बेरोजगारी, कृषि संकट और सामाजिक विघटन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।सवाल यह है कि क्या भारत की ग्राम व्यवस्था अपनी जड़ों से कट रही है? क्या गांव अब केवल सरकारी योजनाओं और चुनावी भाषणों तक सीमित होते जा रहे हैं?

बदलता ग्रामीण भारत

एक समय था जब गांव केवल कृषि उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, लोक संस्कृति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की पहचान हुआ करते थे। गांवों में श्रम का सम्मान था, सामूहिक निर्णय की परंपरा थी और स्थानीय संसाधनों से जीवन चलता था।लेकिन आधुनिक विकास मॉडल ने गांवों की संरचना को तेजी से बदल दिया। शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं के केंद्रीकरण ने शहरों को आकर्षण का केंद्र बना दिया। परिणामस्वरूप गांवों से युवाओं का पलायन बढ़ने लगा।

आज ग्रामीण भारत दो हिस्सों में बंटता दिखाई देता है—एक वह जो गांव छोड़कर शहरों में अवसर तलाश रहा है, और दूसरा वह जो गांव में रहकर संघर्ष कर रहा है।

विकास की विफलता का संकेत

ग्रामीण पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी है। जब गांव का युवा शहर की ओर जाता है, तब गांव अपनी ऊर्जा खो देता है। खेतों में श्रमिक कम होते हैं, पारंपरिक व्यवसाय खत्म होने लगते हैं और सामाजिक संरचना कमजोर पड़ती है।शहरों में भी यह पलायन सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं देता। लाखों लोग झुग्गियों और असंगठित मजदूरी में जीवन बिताने को मजबूर होते हैं।यदि गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय उद्योग विकसित किये जाते, तो शायद यह स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

ग्राम स्वराज की अवधारणा क्यों प्रासंगिक है?

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी, वह आज पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है। गांधी जी मानते थे कि भारत का वास्तविक विकास गांवों की आत्मनिर्भरता से ही संभव है।

ग्राम स्वराज का अर्थ केवल पंचायत चुनाव नहीं, बल्कि ऐसा गांव है—

- जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो
- जहां निर्णय ग्राम सभा करे
- जहां स्थानीय संसाधनों पर गांव का अधिकार हो
- जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गांव के भीतर उपलब्ध हों

लेकिन आज ग्राम स्वराज की अवधारणा कहीं न कहीं सरकारी ढांचे और राजनीतिक केंद्रीकरण के बीच कमजोर होती दिखाई देती है।

लोकतंत्र की जड़ : पंचायत व्यवस्था

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देकर लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। पंचायतों को स्थानीय विकास की धुरी माना गया। किन्तु आज भी अधिकांश पंचायतें वित्तीय और प्रशासनिक निर्भरता से मुक्त नहीं हो सकी हैं। कई स्थानों पर ग्राम सभा की भूमिका सीमित होकर औपचारिकता बन गई है।यदि पंचायतों को वास्तविक अधिकार, प्रशिक्षण और संसाधन मिलें, तो वे ग्रामीण भारत की दिशा बदल सकती हैं। पंचायत केवल निर्माण कार्य कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक नेतृत्व का केंद्र बन सकती है।

ग्रामीण भारत को केवल सहायता नहीं, स्वावलंबन की आवश्यकता है। गांवों में कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, जल संरक्षण, पशुपालन, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा।जब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी पलायन रुकेगा और ग्राम व्यवस्था पुन: जीवंत होगी।आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक नींव बन सकते हैं।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद की भूमिका

ऐसे दौर में अखिल भारतीय पंचायत परिषद जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायती राज की मूल भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित यह संगठन गांव और पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है।परिषद की भूमिका केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक और सामाजिक भी है।

परिषद निम्न क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभा सकती है –

- पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और जागरूकता
- ग्राम सभा को सक्रिय बनाने का अभियान
- ग्रामीण युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ना
- पंचायतों को अधिकारों और योजनाओं की जानकारी देना
- ग्राम स्वराज और ग्राम स्वावलंबन की विचारधारा को पुनर्जीवित करना
- गांवों की समस्याओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाना

यदि पंचायतें मजबूत होंगी, तो लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होंगी।

भारत का भविष्य केवल स्मार्ट सिटी में नहीं, बल्कि मजबूत गांवों में छिपा है। यदि गांव खाली होते गये, तो भारतीय संस्कृति, सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक चेतना भी कमजोर होती जाएगी।आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों को 'पिछड़े क्षेत्र' नहीं बल्कि 'राष्ट्र निर्माण की मूल इकाई' माना जाये। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वावलंबन और सशक्त पंचायत व्यवस्था ही वह मार्ग है, जो भारत को संतुलित और स्थायी विकास की दिशा दे सकता है।और इस परिवर्तन की यात्रा में अखिल भारतीय पंचायत परिषद जैसी संस्थाएं ग्रामीण भारत की नई आशा बन सकती हैं।

पंचायत से राष्ट्र निर्माण तक अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की भूमिका

डॉ रुद्रभानु
(राष्ट्रीय महामंत्री , अखिल भारतीय पंचायत परिषद्)

भारत के लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति गांवों में बसती है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव के रूप में स्थापित किया। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 महत्वपूर्ण विषय सौंपे गए, जिनका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय भागीदारी बढ़ाना और विकास की शक्ति सीधे ग्रामीण समाज तक पहुंचाना था।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार और ग्राम विकास जैसे विषय केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि पंचायतों के माध्यम से इन्हें जनभागीदारी का स्वरूप दिया गया है।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पंचायतें केवल स्थानीय शासन की इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सहभागिता का सबसे व्यापक माध्यम हैं।

पंचायतों को क्यों दिए गए 29 विषय ?

स्वर्गीय बलवंत राय मेहता समिति ने यह स्पष्ट कहा था कि भारत का विकास ऊपर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि नीचे से संचालित होना चाहिए। गांव का विकास गांव की भागीदारी से ही संभव है। इसी विचार को आधार बनाकर पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए ताकि योजनाएं मंत्रालयों और सचिवालयों तक सीमित न रहें, बल्कि गांव की चौपाल तक पहुंचे।

इन विषयों का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाना था। ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास की धुरी बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

> आज भी अनेक पंचायत प्रतिनिधियों को यह जानकारी नहीं होती कि किस योजना के लिए किस विभाग से संपर्क करना है। कई योजनाएं केवल जानकारी के अभाव में गांव तक नहीं पहुंच पातीं। ऐसी स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

पंचायत और शासन के बीच समन्वय

केंद्र और राज्य शासन के लगभग सभी प्रमुख विभाग पंचायतों के 29 विषयों से जुड़े हुए हैं। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, पेयजल, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे विषय पंचायतों की सक्रिय भागीदारी के बिना प्रभावी नहीं हो सकते।

पंचायतें शासन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण सेतु हैं। योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करें और ग्राम सभाएं निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

पंचायतें केवल निर्माण एजेंसी नहीं प्रतिनिधियों में जागरूकता जरुरी

दुर्भाग्यवश लंबे समय तक पंचायतों को केवल सड़क, नाली और भवन निर्माण तक सीमित समझा गया। जबकि संविधान की भावना इससे कहीं अधिक व्यापक है। पंचायतों का दायित्व सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पोषण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय तक फैला हुआ है।यदि पंचायतें 29 विषयों पर गंभीरता से कार्य करें तो गांवों से पलायन कम हो सकता है, स्थानीय रोजगार बढ़ सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। ग्राम सभाओं को सक्रिय कर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जा सकता है।

आज भी अनेक पंचायत प्रतिनिधियों को यह जानकारी नहीं होती कि किस योजना के लिए किस विभाग से संपर्क करना है। कई योजनाएं केवल जानकारी के अभाव में गांव तक नहीं पहुंच पातीं। ऐसी स्थिति में पंचायत

प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यही वह क्षेत्र है जहां सामाजिक संगठनों और पंचायत आधारित संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की राष्ट्रीय भूमिका

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् स्वतंत्र भारत में पंचायती राज और ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने वाले प्रमुख संगठनों में से एक रहा है। पंचायत व्यवस्था के जनक माने जाने वाले बलवंत राय मेहता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा गुलजारी लाल नंदा जैसे विचारकों की प्रेरणा से स्थापित इस संगठन का उद्देश्य पंचायतों को केवल प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जनशक्ति के रूप में विकसित करना रहा है।

आज जब ग्रामीण भारत तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तब परिषद् की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। परिषद् देशभर में पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करने, ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने और पंचायतों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करने का कार्य कर सकती है।राष्ट्रीय स्तर पर परिषद् निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है —

- पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास
- पंचायतों के 29 विषयों पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान
- ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने की पहल
- पंचायतों के अधिकारों और समस्याओं को नीति स्तर तक पहुंचाना
- विभिन्न राज्यों की सफल पंचायतों के अनुभवों का आदान-प्रदान
- महिला एवं युवा नेतृत्व को प्रोत्साहन
- डिजिटल पंचायत और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा
- ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण पर वैचारिक विमर्श विकसित करना

पंचायत जागरूकता की आवश्यकता

आज भारत में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर उन्हें पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति व्यवहारिक रूप में नहीं मिल पाती। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समाज को अपने अधिकारों तथा दायित्वों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद, प्रशिक्षण, शोध और पंचायत आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पंचायतों पर गंभीर विमर्श ही ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है।

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था — ऐसा गांव जो आत्मनिर्भर हो, निर्णय स्वयं ले और विकास की धुरी बने। पंचायतों के 29 विषय उसी ग्राम स्वराज की बुनियाद हैं।आज आवश्यकता केवल योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि पंचायतों को अधिकार, संसाधन और जानकारी देने की है। जब पंचायतें मजबूत होंगी तभी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।अखिल भारतीय पंचायत परिषद् जैसे संगठन यदि पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण समाज और शासन के बीच वैचारिक एवं सामाजिक सेतु का कार्य करें, तो ग्रामीण भारत में एक नया परिवर्तन संभव है। पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सबसे मजबूत नींव हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'अविस्मरणीय यात्रा' पुस्तक का किया विमोचन

महिला पत्रकारों ने नारी शक्ति वंदन के संकल्प को महिला सशक्तिकरण की ओर बताया ऐतिहासिक कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में पत्रकार श्रीमती नीरा साहू द्वारा गुजरात यात्रा पर लिखी गई पुस्तक 'अविस्मरणीय यात्रा' का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती साहू को उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र एवं शासकीय संकल्प के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला पत्रकारों के अध्ययन भ्रमण की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण पत्रकारों की दृष्टि को व्यापक बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा-वृत्तांत पर्यटन प्रेमियों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होगा।

इस अवसर पर सुश्री निशा द्विवेदी, सुश्री चित्रा पटेल, सुश्री लवलीना शर्मा, जनसंपर्क विभाग की उप संचालक डॉ. दानेश्वरी संभाकर, सहायक संचालक सुश्री संगीता लकड़ा एवं सुश्री आमना खातून सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

परिवार, पंचायत और ग्राम स्वराज : एक राष्ट्रीय सामाजिक अभियान

भारतीय समाज में परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि संस्कार, संवाद, सहयोग और जिम्मेदारी की पहली पाठशाला रहा है। परंतु आधुनिक जीवनशैली, आर्थिक दबाव, डिजिटल दूरी और सामाजिक बदलावों के कारण परिवारों में संवाद कम हुआ है। यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो उसकी शुरुआत परिवार से करनी होगी। 'परिवार सभा' इसी सोच पर आधारित अवधारणा है।

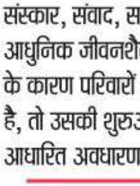

कपिल नारायण अग्रवाल
संयोजक , समाज भारती ,परिवार प्रणाली पुनर्जीवन अभियान , रायपुर

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल संसद, विधानसभाओं और चुनावों तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति गांवों, परिवारों और सामाजिक समरसता में निहित है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 स्पष्ट रूप से राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित करने का निर्देश देता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देकर लोकतंत्र को गांव की चौपाल तक पहुंचाने का प्रयास किया।

किन्तु आज जब ग्रामीण भारत सामाजिक विघटन, पारिवारिक संवादहीनता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, पलायन, सामाजिक अविश्वास और ग्राम सभाओं की निष्क्रियता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब यह आवश्यक हो गया है कि लोकतंत्र को केवल प्रशासनिक ढांचे के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कृति के रूप में पुनर्जीवित किया जाए।

इसी संदर्भ में 'परिवार सभा से ग्राम सभा' का विचार एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पहल के रूप में सामने आता है। यह केवल पंचायत सुधार का प्रस्ताव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक सामाजिक अभियान है।

लोकतंत्र की पहली पाठशाला-परिवार

भारतीय समाज में परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि संस्कार, संवाद, सहयोग और जिम्मेदारी की पहली पाठशाला रहा है। परंतु आधुनिक जीवनशैली, आर्थिक दबाव, डिजिटल दूरी और सामाजिक बदलावों के कारण परिवारों में संवाद कम हुआ है। यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो उसकी शुरुआत परिवार से करनी होगी। 'परिवार सभा' इसी सोच पर आधारित अवधारणा है। प्रत्येक परिवार महीने में एक बार बैठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करे इस प्रक्रिया से परिवार केवल निजी इकाई नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली सक्रिय लोकतांत्रिक इकाई बनेगा। परिवार के भीतर संवाद बढ़ेगा, पीढ़ियों के बीच समझ मजबूत होगी और सामूहिक निर्णय की संस्कृति विकसित होगी।

परिवार प्रतिनिधिः संवाद का नया सेतु

इस मॉडल में प्रत्येक परिवार सहमति से एक 'परिवार प्रतिनिधि' चुनेगा। यह प्रतिनिधि किसी राजनीतिक पदाधिकारी की तरह नहीं, बल्कि परिवार और ग्राम समाज के बीच संवाद का माध्यम होगा। आज गांवों में कई समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि समाज और पंचायत के बीच सीधा संवाद कमजोर हो गया है। परिवार प्रतिनिधि इस दूरी को कम कर सकते हैं। वे ग्राम स्तर की समस्याओं, योजनाओं और आवश्यकताओं को पंचायत तक पहुंचाने के साथ-साथ पंचायत के निर्णयों को समाज तक ले जाएंगे।

ग्राम परिवार मंडल : सामाजिक लोकतंत्र की नई संरचना

जब गांव के सभी परिवार प्रतिनिधि एक साथ आएंगे, तब 'ग्राम परिवार मंडल' का गठन होगा। यह मंडल गांव की सामाजिक चेतना का मंच बन सकता है। इसके माध्यम से ग्राम समस्याओं की पहचान, सामाजिक

विवादों का समाधान, सामूहिक श्रमदान, नशामुक्ति अभियान, जल संरक्षण, ग्राम स्वच्छता और सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसे कार्य सामूहिक रूप से किए जा सकते हैं।यह व्यवस्था ग्राम समाज को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सहभागी और उत्तरदायी नागरिक समाज में बदल सकती है।

ग्राम सभा का पुनर्सशक्तिकरण

आज अनेक स्थानों पर ग्राम सभाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। लोगों की भागीदारी सीमित होती जा रही है और निर्णय प्रक्रिया कुछ लोगों तक सिमटती जा रही है।'परिवार सभा से ग्राम सभा' मॉडल ग्राम सभा को पुन: जीवंत बनाने का प्रयास करता है। ग्राम परिवार मंडल द्वारा तैयार प्रस्ताव ग्राम सभा में प्रस्तुत होंगे, जहां पूरे गांव की सहभागिता से निर्णय लिए जाएंगे।इससे ग्राम सभा वास्तव में ग्रामीण संसद का स्वरूप ले सकेगी। गांव की प्राथमिकताएं गांव स्वयं तय करेगा—चाहे वह जल संरक्षण हो, कृषि नवाचार, स्थानीय रोजगार, विद्यालय सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था या महिला सुरक्षा।

सामाजिक समरसता की दिशा में एक कदम

आज समाज में राजनीतिक और सामाजिक विभाजन लगातार बढ़ रहे हैं। गांवों में भी जातीय तनाव, वैचारिक दूरी और व्यक्तिगत विवाद सामुदायिक एकता को प्रभावित कर रहे हैं। यदि परिवारों और समाज के बीच नियमित संवाद की संस्कृति विकसित होती है, तो यह व्यवस्था सामाजिक समरसता को मजबूत कर सकती है। सामूहिक बैठकों से विवादों का समाधान संवाद के माध्यम से संभव होगा और गांव में सहयोग की भावना विकसित होगी।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद (AIPP) की ऐतिहासिक भूमिका

अखिल भारतीय पंचायत परिषद (AIPP) देश में पंचायती राज संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मंच रहा है। पंचायत सशक्तिकरण, ग्राम स्वराज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में परिषद की ऐतिहासिक भूमिका रही है। AIPP इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में एक समन्वयक संस्था की भूमिका निभा सकती है। परिषद पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, 'परिवार सभा संचालन पुस्तिका' निर्माण, ग्राम नेतृत्व विकास और पंचायत क्षमता निर्माण जैसे कार्यों को आगे बढ़ा सकती है।इसके साथ ही परिषद विभिन्न राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ कर इस मॉडल के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन भी कर सकती है।

डिजिटल ग्राम लोकतंत्र की संभावना

आधुनिक तकनीक का उपयोग इस मॉडल को और प्रभावी बना सकता है। यदि Family Sabha Reporting App, ग्राम विकास डैशबोर्ड और शिकायत-सुझाव प्रणाली विकसित की जाए, तो पंचायतों को वास्तविक समय का सामाजिक डेटा उपलब्ध हो सकेगा।इससे योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी लाने में मदद मिल सकती है।

'एक परिवार-एक सामाजिक उत्तरदाग्राम स्वराज की दिशा में नई पहल'

—'एक परिवार, एक सामाजिक उत्तरदायित्व' सबसे प्रेरक अवधारणाओं में से एक हो सकती है।यदि प्रत्येक परिवार एक पौधा लगाए, एक जल संरक्षण कार्य करे, एक सामाजिक सेवा कार्य अपनाए और ग्राम स्वच्छता में योगदान दे, तो गांव केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का जीवंत केंद्र बन सकता है।

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना ऐसे गांवों की की थी जो आत्मनिर्भर, सहभागी और नैतिक रूप से सशक्त हों। 'परिवार सभा से ग्राम सभा' मॉडल उसी विचार को आधुनिक संदर्भ में पुनर्परिभाषित करता है।यह पहल लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे दैनिक सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाती है। इसमें परिवार सामाजिक शक्ति बनता है, ग्राम सभा निर्णय का वास्तविक मंच बनती है और पंचायत व्यवस्था नैतिक जनभागीदारी का केंद्र बनती है।

'भारत की लोकतांत्रिक शक्ति उसकी जड़ों में बसती है—गांवों में, परिवारों में और सामाजिक एकता में। यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो उसे नीचे से ऊपर तक पुनर्गठित करना होगा।'परिवार सभा से ग्राम सभा' मॉडल इसी दिशा में एक दूरदर्शी और व्यवहारिक प्रयास है। यह केवल पंचायत सुधार का प्रस्ताव नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण का विचार है।यदि अखिल भारतीय पंचायत परिषद (AIPP) इस पहल को राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाती है, तो यह भारत में सहभागी लोकतंत्र, ग्राम स्वराज और सामाजिक समरसता की नई दिशा तय कर सकता है।'

काट कर जेब तुम्हारी

काट कर जेब तुम्हारी,
ख़ैरात बाँटी जा रही है,
और तुम हो कि उन्हें,
अब भी मसीहा समझ रहे हो,
तुम्हारे हिस्से की रोटी,
तुम्हारे ही सामने छीनी गई,
फिर उसी का टुकड़ा देकर,
नेकी की तस्वीर गढ़ी गई,
तालियाँ बजती रहीं,
नारे भी गूंजते रहे,
पर सच्चाई के आईने में,
कुछ चेहरे धुंधले ही रहे,
वो कहते हैं—हमने दिया,
तुम कहते हो—हाँ, उन्होंने दिया,
पर ये कोई क्यों नहीं पूछता,
कि आखिर छीना किसने था ?
तुम्हारे पसीने की कमाई,
कागज़ों में बंट जाती है,
और एहसान के नाम पर,
तुम्हीं को लौटाई जाती है,
ये कैसा न्याय है,
ये कैसी दरियादिली है ?
जहाँ लूट भी इबादत है,
और सवाल करना गुनाह सही है,
उठो, पहचानो सच को,
इन नकाबों के पीछे झाँको,
जो तुम्हारी जेबें काट रहे हैं,
उन्हें मसीहा मत आँको,
क्योंकि जिस दिन समझ आ गया,
हक और ख़ैरात का फर्क,
उस दिन बदल जाएगी तस्वीर,
और टूट जाएगा ये झूठा तर्क,

■ नरेन्द्र पाण्डेय

शुभकामना संदेश

छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के गठन तथा 'लाईफ वर्सिटी' मासिक पत्रिका के माध्यम से पंचायत सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और जनजागरण के उद्देश्य को लेकर विभिन्न जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों एवं प्रबुद्धजनों ने अपनी शुभकामनाएँ एवं समर्थन व्यक्त किया है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव से उनके सरकारी निवास में सौजन्य मुलाकात कर परिषद् के गठन, उद्देश्यों एवं संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर 'लाईफ वर्सिटी' मासिक पत्रिका के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने पत्रिका को शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह शासन की योजनाओं को पंचायत स्तर तक तथा पंचायतों की आवश्यकताओं और समस्याओं को शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का सशक्त माध्यम बनेगी।

कृषि एवं अनुसूचित जाति-जनजाति विकास मंत्री **रामविचार नेताम** ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की मूल इकाई हैं और ग्रामीण विकास का आधार भी। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं, कृषि तकनीकों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की सही जानकारी मिलना आवश्यक है, जिससे गाँवों के विकास को गति मिल सके।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया किअखिल भारतीय पंचायत परिषद्शासन और पंचायतों के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएगी तथा पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक और संगठित करने का कार्य करेगी। श्री नेताम ने कहा कि 'लाईफ वर्सिटी' जैसी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रिका शासन की योजनाओं, पंचायतों के नवाचारों और ग्रामीण विकास की सकारात्मक कहानियों को जन-जन तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री **लक्ष्मी राजवाड़े के OSD चन्द्रवेश सिंह सिसोदिया** से भी सौजन्य मुलाकात कर परिषद् के गठन एवं 'लाईफ वर्सिटी' को परिषद् का मुखपत्र बनाए जाने की जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य संवाद स्थापित करने तथा परिषद् की भावी योजनाओं पर सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। सिसोदिया ने आश्वासन दिया कि मंत्री जी के प्रवास से लौटने के पश्चात शीघ्र ही विस्तृत चर्चा हेतु मुलाकात कराई जाएगी।

पूर्व विधायक **विनोद चंद्राकर** ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों के विकास के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि नरेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व एवं 'लाईफ वर्सिटी' की लेखनी के माध्यम से गांवों की समस्याएँ शासन-प्रशासन तक और शासन की योजनाओं की जानकारी जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचेगी।

रायपुर उत्तर के विधायक **पुरंदर मिश्रा** ने कहा कि वे नरेन्द्र पाण्डेय के साथ स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्यों में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनकी सहजता, प्रभावी संवाद कौशल और समाज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति उनकी चिंतनशील लेखनी लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।विधायकमिश्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद् में प्राप्त दायित्व का निर्वहन नरेन्द्र पाण्डेय पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 'लाईफ वर्सिटी' मासिक पत्रिका ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगी।

रायपुर ग्रामीण के विधायक **मोतीलाल साहू** ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों को अधिकार तो मिले, लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में ग्राम पंचायतें अपेक्षित रूप से सशक्त नहीं हो पाई हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ में नरेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों के लिए सार्थक संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे ग्राम सभाएँ मजबूत होंगी और गांव आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।

राज्य के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ **डॉ अनिल गुप्ता** ने कहा कि वे नरेन्द्र पाण्डेय को पिछले 12-13 वर्षों से जानते हैं और उनके सामाजिक नेतृत्व, सक्रिय कार्यशैली तथा सशक्त लेखन पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि 'लाईफ वर्सिटी' के माध्यम से राज्य के ग्राम विकास, जनजागरण और सामाजिक सरोकारों को नई दिशा मिलेगी। डॉ गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पत्रिका पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और समाज के बीच सकारात्मक संवाद का प्रभावी मंच बनेगी। उन्होंने इस रचनात्मक पहल की सराहना करते हुए कहा कि वे स्वयं भी इस सकारात्मक अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

पूर्व कृषि मंत्री **चन्द्रशेखर साहू** ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और ग्रामोदय से ही सर्वोदय संभव है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तथा नरेन्द्र पाण्डेय और 'लाईफ वर्सिटी' की पहल सराहनीय है।

छत्तीसगढ़ शासन में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के OSD शलभ साहू से सौजन्य मुलाकात हुई। इस दौरान उन्हें अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की गतिविधियों एवं छत्तीसगढ़ इकाई के गठन के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

मुलाकात के दौरान श्री साहू ने 'लाईफ वर्सिटी' पत्रिका को CGAIPP का मुखपत्र बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित योजनाओं, जनकल्याणकारी गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को 'लाईफ वर्सिटी' के माध्यम से पंचायत स्तर तक पहुँचाना एक सराहनीय पहल होगी।

RIMS Medical College के डीन **डॉ गंभीर सिंह** ने कहा कि वे वर्ष 2012 से नरेन्द्र पाण्डेय के साथ स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक उत्थान से जुड़े विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र पाण्डेय की सहज कार्यशैली, प्रभावी संवाद कौशल तथा समाज और गांवों के प्रति उनकी चिंतनशील लेखनी लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने में सक्षम है।डॉ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया किअखिल भारतीय पंचायत परिषद्में मिले दायित्व का निर्वहन नरेन्द्र पाण्डेय पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि 'लाईफ वर्सिटी' मासिक पत्रिका पंचायतों, ग्रामीण समाज और जनजागरण के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अनामिका पाण्डेय

हर काल में महिलाएं ही क्यों बनती है मोहरा

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल आरक्षण नहीं, बल्कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सम्मान है। जब तक राजनीतिक दल अपने भीतर लोकतंत्र और समान अवसर की संस्कृति विकसित नहीं करेंगे, तब तक कानून केवल प्रतीक बनकर रह जाएंगे।

भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसका राजनीतिक उपयोग भी गंभीर बहस का विषय बन चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को अपने-अपने राजनीतिक हितों के अनुसार इस्तेमाल किया है। फर्क केवल इतना है कि कोई इसे 'नारी शक्ति' कहता है, तो कोई 'समान अधिकार'। लेकिन जमीनी सच यह है कि आज भी राजनीति में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सीमित और प्रतीकात्मक ही दिखाई देती है।

महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक कदम बताया गया, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हुए। क्या यह वास्तव में महिलाओं को निर्णयकारी शक्ति देने का प्रयास है, या फिर आने वाले चुनावों से पहले आधी आबादी को भावनात्मक रूप से साधने की रणनीति? यदि राजनीतिक दल सचमुच महिलाओं की बराबरी चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने संगठन और टिकट वितरण में समान अवसर देने चाहिए। संसद में कानून बना देना आसान है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति बदलना कठिन।

भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से 'संस्कृति', 'परंपरा' और 'नारी सम्मान' को अपने राजनीतिक विमर्श का बड़ा आधार बनाया है। वहीं विपक्ष ने भी महिला अधिकारों के मुद्दे को अक्सर केवल सरकार विरोध तक सीमित रखा। जब किसी राज्य में महिला उत्पीड़न की घटना होती है, तब दोनों पक्ष घटना को संवेदना से अधिक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर स्थायी नीति कम, राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा दिखती है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए हमारे पौराणिक आख्यानों का भी अक्सर उल्लेख किया जाता है। रामायण में सीता त्याग, मर्यादा और धैर्य का प्रतीक बनती हैं, लेकिन उसी कथा में उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्निपरीक्षा भी देनी पड़ती है। महाभारत में द्रौपदी के अपमान पर पूरा युद्ध खड़ा हो जाता है, परंतु सभा में बैठे महान योद्धा और नीति के ज्ञाता मौन रहते हैं। ये उदाहरण केवल धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक भी हैं जिसमें महिला का सम्मान अक्सर पुरुष सत्ता और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा गया।

आज भी राजनीति में महिलाओं को कई बार 'सम्मान' तो दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्र नेतृत्व कम दिया जाता है। उन्हें मंच पर स्थान मिलता है, पर निर्णय प्रक्रिया में बराबरी कम मिलती है। कई दलों में महिला नेता तभी प्रमुखता पाती हैं जब उन्हें किसी विशेष राजनीतिक संदेश या भावनात्मक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना हो। यह स्थिति केवल एक दल की नहीं, लगभग पूरे राजनीतिक तंत्र की सच्चाई है।

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल आरक्षण नहीं, बल्कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सम्मान है।

जब तक राजनीतिक दल अपने भीतर लोकतंत्र और समान अवसर की संस्कृति विकसित नहीं करेंगे, तब तक कानून केवल प्रतीक बनकर रह जाएंगे। भारत की महिलाएं आज विज्ञान, सेना, न्यायपालिका, खेल, प्रशासन और उद्योग हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं। उन्हें दया, संरक्षण या प्रतीकात्मक सम्मान नहीं, बल्कि बराबरी का अवसर चाहिए। राजनीति यदि सचमुच महिला शक्ति का सम्मान करना चाहती है, तो उसे महिलाओं को वोट बैंक नहीं, नेतृत्व शक्ति मानना होगा।

क्या महिलाएं सचमुच सशक्त हुई हैं?

Dr Shubhra Sanyal,
Former Senior Reader
(Sociology) NICFS)
MHA New Delhi

सभ्यता के विकास, तकनीकी प्रगति और 'महिला सशक्तिकरण' के बड़े-बड़े नारों के बीच एक सवाल आज भी समाज के सामने खड़ा है—क्या महिलाएं सचमुच सशक्त हुई हैं, या यह केवल आधुनिकता का चमकदार भ्रम है?

आज महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर सेना, राजनीति, पत्रकारिता, चिकित्सा, न्यायपालिका और कॉर्पोरेट जगत तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन जब हम मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो तस्वीर उतनी उजली नहीं दिखाई देती। विशेषकर भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं आज भी कई अदृश्य दीवारों से घिरी हुई हैं। इन्हें ही आधुनिक समाजशास्त्र में 'ग्लास सीलिंग' कहा जाता है—एक ऐसी पारदर्शी बाधा जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महिलाओं की प्रगति को रोकती रहती है।

एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में जब हम महिलाओं की मानसिक स्थिति, सामाजिक दबाव और कार्यस्थलों पर होने वाले व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के लिए संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत भी है।

आज भी अधिकांश कार्यस्थल 'जेंडर फ्रेंडली' नहीं हैं। महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, नेतृत्व के अवसरों की कमी और प्रभावशाली नेटवर्क तक सीमित पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक पुरुष यदि देर रात तक काम करे तो उसे 'समर्पित' कहा जाता है, लेकिन वही काम महिला करे तो उसके चरित्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर प्रश्न उठाए जाते हैं।

समाज ने महिलाओं के लिए सदियों से कुछ निश्चित भूमिकाएं तय कर रखी हैं—घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार के लिए त्याग करना। यही कारण है कि जब कोई महिला अपने करियर को प्राथमिकता देती है तो उसे अक्सर 'स्वार्थी' या 'परिवार विरोधी' कहकर देखा जाता है। यह मानसिकता महिलाओं के आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ती है।

कई संगठनों में आज भी छोटे बच्चों की माताओं के लिए उचित चाइल्ड केयर सुविधाएं नहीं हैं। परिणामस्वरूप अनेक प्रतिभाशाली महिलाएं अपने उभरते करियर को छोड़कर घर बैठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जो महिलाएं तमाम बाधाओं को पार कर ऊंचे पदों तक पहुंचती भी हैं, वे अक्सर अकेली पड़ जाती हैं। उनके आसपास ऐसे मित्र, मार्गदर्शक या सहयोगी नहीं होते जिनसे वे खुलकर संवाद कर सकें। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी वे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं।

लेकिन सबसे भयावह पक्ष है—कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न।

यौन शोषण केवल शारीरिक अपराध नहीं है, यह मानसिक नियंत्रण और सत्ता प्रदर्शन का हथियार भी है। एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में यह समझना आवश्यक है कि ऐसे अपराधों के पीछे केवल कामुकता नहीं, बल्कि प्रभुत्व की मानसिकता कार्य करती है। वरिष्ठ अधिकारी, प्रोफेसर, कोच या प्रभावशाली पुरुष अक्सर अपने पद और शक्ति का उपयोग महिलाओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए करते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारी और पिछड़े वर्गों से आने वाली महिलाएं इस शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वे विरोध नहीं कर पातीं क्योंकि उन्हें नौकरी जाने, बदनामी और सामाजिक बहिष्कार का डर होता है। यही भय अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

वर्षों पहले कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर किए गए अध्ययन में यह सामने आया था कि अधिकांश महिलाएं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को सार्वजनिक करने से डरती हैं। दुखद यह है कि दो दशक बाद भी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। आज भी समाचार पत्रों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां छात्राओं, इंटर्न्स, महिला कर्मचारियों और युवा प्रोफेशनल्स का शोषण 'प्रमोशन', 'स्थायी नियुक्ति' या अन्य सुविधाओं के लालच में किया जाता है।

आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटलजैसी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में हुई दरिंदगी केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि यह उस सामाजिक मानसिकता का प्रतिबिंब थी जिसमें महिला की सुरक्षा आज भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसे अनेक मामले समाज की चुप्पी और पीड़िता के भय के कारण दबा दिए जाते हैं।

मनोविज्ञान बताता है कि लगातार भेदभाव और उत्पीड़न महिलाओं के 'सेल्फ कॉन्सेप्ट' यानी आत्म-छवि को गहराई से प्रभावित करता है। जब किसी महिला को बार-बार यह महसूस कराया जाता है कि वह पुरुष से कम सक्षम है, तो उसके भीतर अपराधबोध, हीनभावना, तनाव और अवसाद जन्म लेने लगते हैं। कई बार महिलाएं स्वयं अपनी क्षमता पर संदेह करने लगती हैं। यही मानसिक दासता किसी भी समाज की सबसे बड़ी विफलता है।

विडंबना यह है कि समाज महिलाओं से 'सब कुछ' चाहता है—वे सफल प्रोफेशनल भी हों, आदर्श पत्नी भी, समर्पित मां भी और हर समय सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाली भी। लेकिन जब कोई महिला इन सभी भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, तो वही समाज उसे कठघरे में खड़ा कर देता है।

सच्चा महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने या मंचों से भाषण देने से नहीं आएगा। इसके लिए समाज की मानसिक संरचना बदलनी होगी। कार्यस्थलों को सुरक्षित और संवेदनशील बनाना होगा। महिलाओं को केवल अवसर नहीं, बल्कि सम्मान और मानसिक सुरक्षा भी देनी होगी।

जब तक एक महिला बिना भय, बिना भेदभाव और बिना समझौते के अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक 'महिला सशक्तिकरण' अधूरा ही रहेगा।

आज आवश्यकता केवल महिलाओं को मजबूत बनाने की नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदलने की है। क्योंकि जिस दिन समाज महिला को 'अधिकार' नहीं बल्कि 'समान अस्तित्व' के रूप में स्वीकार कर लेगा, उसी दिन वास्तविक सशक्तिकरण की

हार में छिपी कांग्रेस की खामोश जीत की आहट

■ नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

पश्चिम बंगाल से लेकर असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी तक फैले 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे पहली नजर में भले ही एकतरफा कहानी कहते दिखें—सत्ता के सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी का परचम, और क्षेत्रीय क्षत्रपों की पराजय। लेकिन राजनीति का असली खेल हमेशा सतह के नीचे चलता है। आंकड़ों की तह में उतरें, तो एक दूसरी कहानी उभरती है—धीमी, मगर निर्णायक। यह कहानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुनरुत्थान की, जो शोर नहीं करती, पर दिशा बदलने की ताकत रखती है।

यह चुनाव परिणाम एक विरोधाभास की तरह हैं। सत्ता भले बीजेपी के खाते में गई हो, लेकिन 'संभावनाओं की जीत' कांग्रेस के हिस्से आई है। राजनीति में कभी-कभी हार, भविष्य की सबसे बड़ी जीत की प्रस्तावना होती है—और 2026 के नतीजे उसी प्रस्तावना की तरह हैं।

केरल ने इस कथा को सबसे स्पष्ट रूप में सामने रखा। एक दशक बाद सत्ता में वापसी कर कांग्रेस ने यह साबित किया कि दक्षिण भारत में उसका संगठन और सामाजिक आधार अभी भी मजबूत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 'वायनाड प्रभाव' ने सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं बदले, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरी है। यह जीत केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि मनोबल की वापसी है—एक ऐसी संजीवनी, जिसकी कांग्रेस को लंबे समय से तलाश थी।

पश्चिम बंगाल में परिदृश्य और भी दिलचस्प है। ममता बनर्जी के किले के ढहने के बाद जो सियासी शून्य बना है, वह केवल बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी अवसर का द्वार खोलता है। भले ही कांग्रेस की सीटें कम हों, लेकिन वोट शेयर में बढ़ोतरी और राजनीतिक उपस्थिति का पुनः स्थापित होना संकेत देता है कि वह फिर से 'स्वाभाविक विपक्ष' की भूमिका में लौट सकती है। बंगाल की राजनीति अब त्रिकोणीय नहीं, बल्कि धीरे-धीरे द्विध्रुवीय होती दिख रही है—जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी हो सकती है।

असम में कहानी और भी स्पष्ट है। बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी के प्रभाव में गिरावट ने कांग्रेस के लिए रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से बंटे हुए अल्पसंख्यक वोटों का एकमुश्त कांग्रेस की ओर झुकाव, भविष्य की राजनीति को 'बाइपोलर' बनाने की ओर इशारा करता है। यहां बीजेपी की जीत जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण कांग्रेस की स्थिति का मजबूत होना भी है।

तमिलनाडु में दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति के बीच एक नई हलचल दिखी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के वर्चस्व के बीच, नए चेहरों का उभार और कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश यह संकेत देती है कि राज्य की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस, जो लंबे समय से 'जूनियर पार्टनर' बनकर रह गई थी, अब खुद को एक स्वतंत्र और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है।

इन चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारतीय राजनीति में एक 'साइलेंट शिफ्ट' चल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होते हैं। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन पूरी तरह वापस भले न पाई हो, लेकिन उसने उस जमीन पर दोबारा कदम जरूर रख दिया है। और राजनीति में वापसी की शुरुआत अक्सर इसी पहले कदम से होती है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जनादेश सत्ता की पुष्टि है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह संभावनाओं का द्वार खोलता है। आज का चुनाव परिणाम अगर वर्तमान का आईना है, तो आने वाले 2029 का चुनाव भविष्य की पटकथा लिखेगा—और उस पटकथा में कांग्रेस अब फिर से एक केंद्रीय पात्र के रूप में उभरती दिख रही है।

राजनीति का इतिहास गवाह है—जब-जब क्षेत्रीय ताकतें कमजोर हुई हैं, कांग्रेस ने 'फीनिक्स' की तरह राख से उठकर वापसी की है। 2026 के नतीजे उसी वापसी की प्रस्तावना हैं। सत्ता के शोर में भले यह आवाज दब जाए, लेकिन आने वाले वर्षों में यही 'खामोश जीत' भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच बन सकती है।

पिंजड़े का बंद तोता या पहाड़ी मैना ?

समीर दुबे
एडिटर छत्तीसगढ़
K News India

भारतीय लोकतंत्र में कुछ उपमाएं समय के साथ और तीखी होती जाती हैं। 2013 में PA काल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI को 'पिंजड़े का बंद तोता' कहे जाने के बाद अब विपक्ष इसे आगे ले गया है। उनका नया तंज है कि तोता पुराना पड़ गया — अब पहाड़ी मैना का जमाना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना इंसानी आवाज की हूबहू नकल करता है — जितना सिखाओ, वैसा ही दोहराता है।विपक्ष का आरोप है कि CBI, ED, IT के साथ-साथ निर्वाचन आयोग भी अब इसी श्रेणी में आ गया है।

2026 के विधानसभा चुनावों (खासकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि) में BJP के मजबूत प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों ने एक स्वर में संस्थाओं पर सवाल उठाए।

- **राहुल गांधी (कांग्रेस)**- उन्होंने निर्वाचन आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, "Election Commission gaslighting citizens है, इससे लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो रहा है। 'वोट चोरी एंटी नेशनल एक्ट है।' राहुल ने CBI, ED और EC को एक साथ जोड़ते हुए आरोप लगाया कि सरकार इन संस्थाओं का इस्तेमाल चुनावी नतीजों को "shape" करने के लिए कर रही है। उन्होंने "systematic vote theft" और voter list में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया।
- **अरविंद केजरीवाल (AAP)**- केजरीवाल ने कहा, 'अब कहने की भी जरूरत नहीं कि Election Commission BJP के अधीन काम कर रहा है। यह अब openly हो चुका है।' उन्होंने CBI-ED को 'BJP के हथियार' बताया और आरोप लगाया कि ये एजेंसियां विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि EC चुनावी मैदान में BJP का साथ दे रहा है।
- **अखिलेश यादव (सपा)**- अखिलेश ने EC पर "bias और fraud in electoral rolls" का आरोप लगाते हुए कहा कि opposition voters के नाम फर्जी Form-7 के जरिए हटाए जा रहे हैं। उन्होंने CBI-ED पर भी हमला बोलते हुए कहा कि BJP opposition शासित राज्यों में इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनावी transparency को खत्म कर रही है।
- ममता बनर्जी, DMK और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इन बयानों का समर्थन किया और "Raid Raj" तथा "Vote Chori" के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया।

पुरानी समस्या, व्यापक संदर्भ

- **केंद्रीय एजेंसियां** - CBI-ED की स्वायत्तता पर सवाल पुराने हैं। नियुक्ति, फंडिंग और नियंत्रण केंद्र के पास होने से 'मालिक की आवाज' वाला आरोप लगता रहा है।
- **निर्वाचन आयोग** - संवैधानिक संस्था होने के बावजूद विपक्ष इसे केंद्र पर निर्भर बताता है — नियुक्ति प्रक्रिया और वित्तीय निर्भरता को लेकर।

सत्ताधारी पक्ष का जवाब- ये संस्थाएं कानून के अनुसार काम करती हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई या मतदाता सूची शुद्धिकरण को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।

लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी

पहाड़ी मैना हो या बंद तोता — समस्या पिंजड़े की है। जब तक संस्थाओं की संरचनात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित नहीं होगी, सत्ता बदलने पर यही आरोप-प्रत्यारोप जारी रहेगा।

CBI/ED के लिए स्वतंत्र चयन, निश्चित कार्यकाल और जवाबदेही। निर्वाचन आयोग के लिए पारदर्शी नियुक्ति, पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता और मजबूत संवैधानिक सुरक्षा। की मांग उठती रहती है । सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि ये संस्थाएं "CaesarÓs wife" की तरह — शक के ऊपर होनी चाहिए। 2026 चुनावों के बाद विपक्ष की ये तीखी टिप्पणियां एक बार फिर याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि प्रक्रिया का विश्वास भी जरूरी है।

चाहे CBI हो, ED हो या निर्वाचन आयोग — जब ये 'सिखाए अनुसार' काम करते दिखें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। असली चुनौती पिंजड़े को खोलने की है, न कि पक्षी बदलने की। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हर संस्था को कानून और संविधान की रखवाली करनी चाहिए, किसी खास 'मालिक' की नहीं। यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष — दोनों की है।

दिमाग की सेटिंग बदलो, जिंदगी बदल जाएगी

■ डॉ अनिल कुमार गुप्ता
डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एवं पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन

मनुष्य अपने पूरे जीवन में जिस चीज़ के सहारे जीता है, वह है उसका मन और मस्तिष्क। उसी से वह सोचता है, निर्णय लेता है, रिश्ते बनाता है और अपने भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि हमारा दिमाग वास्तव में काम कैसे करता है।

न स्कूल में, न कॉलेज में, और न ही समाज में।

हमें मशीनें चलाना सिखाया जाता है, तकनीक सिखाई जाती है, लेकिन उस 'मानसिक मशीन' को समझना नहीं सिखाया जाता जिसके सहारे पूरी जिंदगी चलती है। शायद यही कारण है कि आज अधिकांश लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से तनाव, चिंता, असुरक्षा और मानसिक संघर्ष से भरे होते हैं।

यदि गहराई से देखा जाए तो मानव मस्तिष्क किसी आधुनिक मोबाइल फोन या कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे किसी डिवाइस में अलग-अलग ऐप्स, सॉफ्टवेयर और सेटिंग्स होती हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी मानसिक प्रोग्रामिंग मौजूद होती है। बचपन से लेकर आज तक जो बातें हमने सुनीं, जिन अनुभवों से गुजरे और जिन परिस्थितियों में रहे, उन्होंने हमारे भीतर सोचने का एक तरीका बना दिया।

पुरानी आदतें उन 'प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स' की तरह हैं जिन्हें हमने खुद नहीं चुना।

सीमित करने वाले विश्वास पुराने सॉफ्टवेयर की तरह हैं जो हमारी गति रोकते रहते हैं।

तनाव उस स्थिति जैसा है जब दिमाग में एक साथ बहुत सारे टैब खुले हों और नकारात्मक सोच उस छिपे हुए वायरस की तरह है जो धीरे-धीरे आत्मविश्वास और ऊर्जा को खत्म करता रहता है।

आज कई लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भीतर बैठे पुराने विश्वास उन्हें रोकते रहते हैं। जैसे—

'मैं यह नहीं कर सकता।'

'मेरे पास अवसर नहीं हैं।'

'लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे।'

धीरे-धीरे ये विचार व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। फिर दिमाग उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद खुद पर भरोसा नहीं कर पाते।

यहीं पर न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। NLP यह समझने की प्रक्रिया है कि हमारी भाषा, सोच और भावनाएँ हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। यह हमें बताता है कि यदि मानसिक पैटर्न बदले जाएँ, तो जीवन का अनुभव भी बदल सकता है।

विज्ञान भी अब यह मानता है कि मस्तिष्क स्थिर नहीं है। उसमें बदलने की क्षमता होती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अर्थात यदि व्यक्ति नई सोच, नए व्यवहार और नए अनुभवों को लगातार दोहराए, तो मस्तिष्क नए न्यूरल मार्ग बनाना शुरू कर देता है।

यही कारण है कि कोई व्यक्ति धीरे-धीरे अपने पुराने डर और सीमित विश्वासों से बाहर निकल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा मानता रहा कि वह लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो वह छोटे-छोटे प्रयासों से शुरुआत कर सकता है। मीटिंग में अपनी बात रखना, किसी समूह में प्रश्न पूछना या अपने विचार साझा करना—ये छोटे अनुभव धीरे-धीरे दिमाग को नया संदेश देते हैं कि 'मैं सक्षम हूँ।'

समस्या यह नहीं कि लोगों के पास क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग पुराने मानसिक प्रोग्राम पर चल रहे हैं।

आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, बल्कि अपने मानसिक ढाँचे को समझने की है। क्योंकि यदि मन ही बिखरा हुआ हो, तो बाहरी सफलता भी भीतर शांति नहीं दे सकती।

इसलिए अब समय आ गया है कि हम केवल अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट न करें, बल्कि अपने मानसिक सिस्टम को भी अपडेट करें। पुराने डर हटाएँ, सीमित विश्वासों को अनइंस्टॉल करें और नई संभावनाओं को इंस्टॉल करें।

जब सोच बदलती है, तब दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है, तब निर्णय बदलते हैं और जब निर्णय बदलते हैं, तब धीरे-धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है।

मनुष्य केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है; वह अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को बदलने की क्षमता भी रखता है। इसलिए अपने भीतर चल रहे 'ऑपरेटिंग सिस्टम' को समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की सेटिंग बदलना सीख जाता है, वह अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है।

www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic Health Care System

Unique Wellbeing Center

Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing

MIND BRAIN BODY SOUL
M.B.B.S

1. **Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-**

   Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.

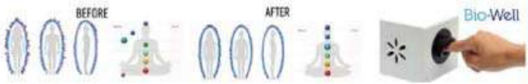

2. **Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -**

   Personality Analysis Body Type, Mind Type, Energy Type.

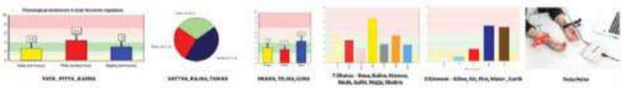

3. **Life Style Clinic**

   Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.

4. **Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.**

5. **Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.**

6. **Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.**

Get In Touch
9109185028, 9109185025

A-41, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com

सुशासन तिहार 2026
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
सुशासन तिहार 2026
01 मई से 10 जून 2026
गाँव-गाँव, द्वार-द्वार
सुशासन की सरकार
जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों, जमीन संबंधी मामलों एवं प्रमाण–पत्र से जुड़ी समस्याओं का निराकरण
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन
संवाद- 13794/2
उद्देश्य
समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध समाधान
विकास कार्यों को मिलेगी गति
जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
पारदर्शिता और जवाबदेही से 'जनकल्याण' होगा सुनिश्चित
संवाद से संपूर्ण समाधान
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in